नंदीग्राम नरसंहार

वामपंथियों का खूनी खेल

प्रकाशकीय

नंदीग्राम नरसंहार भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। पिछले लगभग ६-७ माह से पश्चिम बंगाल में सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक वामपंथी सरकार ने जमीन अधिग्रहण को लेकर निरीह गरीब किसानों पर जो अत्याचार किये, उसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड, स्टालिन की बर्बरता आदि कई घटनाओं से की गयी जो अतिश्योक्ति नहीं है।

ग़ौरतलब है कि नंदीग्राम में इंडोनेशियाई औद्योगिक घराने सलीम समूह के प्रस्तावित रासायनिक कारखानों के लिए वामपंथी सरकार किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है। बड़ी संख्या में किसान इस □ू-अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। गत १४ मार्च, २००७ को नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाम मोर्चा सरकार के इशारे पर पुलिस ने जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें कम से कम १५ लोग मारे गए और २०० से अधिक घायल हो गए।

हांलाकि इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में वामपंथी सरकार अकेली नहीं है बल्कि परोक्ष रूप से कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की मौन स्वीकृति है। भले ही कांग्रेस की स्थानीय इकाई इस घटना की निंदा करती हो, कुछ कांग्रेसी नेता भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो, सोनिया गांधी को जांच रिपोर्ट की प्रति सौंपी जा रही हो, पर प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी जो निर्णय लेने में सक्षम लोग हैं वे चुप्पी साधे बैठे हैं। मामला साफ है मजबूर किसानों के खून से सने वामपंथियों के हाथ में यूपीए सरकार की बागडोर है और कांग्रेस किसानों की लाश का सौदा कर सत्ता में बनी रहना चाहती है। क्योंकि यदि कांग्रेस कोई भी कदम उठाती है तो, (सीताराम यचुरी के बयान के अनुसार) संभव है केन्द्र की सरकार सत्ता से बेदखल हो जाए। यही कारण है कि जहां बंगाल के राज्यपाल जिस घटना की खुली भर्त्सना कर रहे हों, राष्ट्रपति कलाम सार्वजनिक रूप से दुख जता रहे हो, बंगाल हाईकोर्ट तत्काल जांच का आदेश पारित कर सीबीआई को जांच करने का आदेश दे रही हो, संयुक्त रूप से विपक्ष कार्यवाही की मांग कर रहा हो, वहां केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई किये जाने की बात तो दूर बल्कि संसद में विपक्ष की मांग पर बहस भी न होने दी जाए, पोल खुलने के भय से सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया जाए, यह साबित करता है कि वामपंथी और कांग्रेसी दोनों ''चोर-चोर मौसेरे भाई हैं''। यही नहीं पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार जो खूनी खेल खेल रही है उसे परोक्ष रूप से सह देने का काम कांग्रेस ही कर रही है।

इन तमाम विषयों पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने एक स्वर में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाचार पत्रों ने अपने सम्पादकीय और समाचारों के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को परत-दर-परत खोल कर रख दिया है। वहीं देश के तमाम विद्वतजनों से अपनी लेखनी से इस घटना की तीव्र भर्त्सना भी की है। हम यहां उनमें से कुछ लेख व समाचार आदि संकलित कर एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं।

आशा है यह पुस्तिका मार्क्सवादियों के किसान-मजदूर विरोधी चेहरा को उजागर करने में सहायक सिद्ध होगी।

i¡dk'kd
Hkkjrh; turk ikVh

राजग का ज्ञापन : नंदीग्राम नरसंहार

राष्ट्रपतिजी से नंदीग्राम में माकपा शासन का 'सच' देखने की अपील

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में वाममोर्चा सरकार द्वारा किसानों के नरसंहार के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने महामहिम राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय से अपील की गई है कि वे केन्द्र सरकार पर संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का दबाव डालें। प्रस्तुत है ज्ञापन का पूरा पाठः—

महामहिम राष्ट्रपतिजी,

राजग के हम संसद सदस्य, आपका ध्यान पश्चिम बंगाल स्थित पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम व इसके आसपास मौजूदा भयावह हालात की ओर आकृष्ट करने का अनुरोध करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, १४ मार्च, २००७ को राज्य-पुलिस प्रदेश शासक दल के शस्त्रधारी कैडरों के साथ मिलकर निःसहाय ग्रामीणों पर भयानक जुल्म ढ़ाया।

आधिकारिक स्रोत भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पुलिस व पार्टी कैडरों के अंधाधुंध गोलीबारी में १४ व्यक्तिओं की मौत हुई और ३५ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यही नहीं, कम से कम ५० घायल लोग विभिन्न अस्पतालों में अब भी इलाज करवा रहे हैं। जैसा कि पुलिस ने स्वीकार किया है कि उसने २० राउंड गोलियां चलाईं, लेकिन गोली से हुई मौतें व घायलों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि इस नरसंहार में प्रदेश शासकदल के कैडरों की सक्रिय भागीदारी थी।

हकीकत

राष्ट्रपतिजी, प्रतिपक्ष दल के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार, १७ मार्च को प्रभावित गांव का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने जो कुछ भी वहां देखा-सुना, उससे वह भौचक्का रह गया। सर्वाधिक प्रभावित गांवों में से एक सोनाचुरा गांव में प्रतिनिधिमंडल को अपनी दास्तां सुनाने के लिए लगभग १०,००० लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ग्रामवासी तो फूट-फूट कर रोने लगा जब उसने बताया कि किस प्रकार से पुलिस की गोली ने मेरे भाई के शरीर के चिथड़े-चिथड़े कर दिए। जब घायल व्यक्ति को उसके परिवार के लोग गांव वापस ले जा रहे थे तो पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती उसे छीन लिया। अभी तक इस क्षेत्र में उसका पता नहीं लग पाया है, यहां तक कि अस्पतालों में

उसकी तलाश बेकार रही है।

महामहिमजी विभिन्न गांवों के लोगों ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि उस दुर्भाग्यशाली दिन खेतों में प्रार्थना सभाएं आयोजित कर अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए हिन्दुओं ने भगवान ''गौरंगा'' की मूर्ति की स्थापना की थी और मुसलमानों ने कुरान की आयतों का पाठ किया था क्योंकि उन्हे डर था कि राज्य सरकार सेज की स्थापना के लिए जबर्दस्ती उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लेगी। ग्रामवासियों ने कहा कि पुलिस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने इन प्रार्थना सभाओं पर हमले किए। सभी लोगों ने बताया कि पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भागते ग्रामवासियों पर जान से मार डालने के इरादे से गोलियां चलाई, जिनमें महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल थे। यह देखते हुए कि सभी मृतकों तथा घायल लोगों पर जो गालियां लगी हैं, वे कमर से ऊपर के हिस्से में लगी हैं, जिससे हमला करने वालों का हत्या करने का इरादा साफ दिखाई पड़ता है।

प्रतिनिधिमंडल नंदीग्राम ग्रामीण हस्तपाल तथा तमलुक गर्वनमेंट अस्तपाल भी गए, जहां अनेक घायल लोगों से मुलाकात की। टीम को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि 'पुलिस ब्ल्यू बुक' का पूरा उल्लंघन हुआ। यहां तक कि वहां पर एंबुलेंस व फायरब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी। घायलों को साइकिल, रिक्शा और यहां तक कि उन्हें कंधों पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, इसी कारण घायलों को उनके चिकित्सा-उपचार में बहुत देर हुई।

बलात्कारी पुलिसकर्मी

वर्दीधारी पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किए जाने का आरोप तो और भी दुख पहुंचाता है। एक गांव में, एक बुजुर्ग महिला का आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने दो युवतियों के साथ उनकी आंखों के सामने से बलात्कार किया। एक दूसरे स्थान पर, प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने गौशाला में भागती हुई महिला का पीछा किया। साथ ही हिंसा में घायल हुई एक और महिला का बलात्कार किया गया, जिसके मामले बताया गया कि वह बेहोश पड़ी थी। क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, हस्पताल ने उसकी चिकित्सा जांच भी नही की। आखिरकार जब शिकायत दर्ज हुई और चिकित्सा जांच का आदेश दिया गया तब तक तो ४८ घंटे गुजर गए थे, जिसके कारण इस जघन्य अपराध का आरोप स्थापित करना मुश्किल हो गया।

हमारी अपील

राष्ट्रपतिजी, आप वर्तमान राजनैतिक यथार्थ से वाकिफ हैं, जिसके कारण भारत सरकार इस विषय को कोई उपाए करने तथा उस राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने में कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा पा रही है। हम जानते हैं कि इसमें यूपीए का एक प्रमुख दल शासन चला रहा हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि जहां एक तरफ राज्यपाल श्री गोपालकृष्ण गांधी ने अपनी आत्मा की आवाज के कारण इस रक्तपात पर अपना गहरा रोष

प्रगट किया और आपने भी अप्रत्यक्ष रूप से जबरदस्ती भू-अधिग्रहण की आलोचना की है, इतना ही नहीं तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत की संसद को जलियांवाला बाग में घटी घटना के बाद, आज तक की निकृष्टतम घटना पर चर्चा करने से भी रोका जा रहा है।

श्रीमन् नंदीग्राम में अभी तक आतंक का माहौल छाया हुआ है और सैंकड़ों लोग अपने घरों से गायब हैं। ग्रामवासियों में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का भय बना हुआ है, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप सरकार पर संविधान के अनुच्छेद ३५५ के संगत खंडों को लागू करने का दबाव डालें और :

१. पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दें कि वह तुरंत ही इस क्षेत्र में हिंसा की निरंतर घट रही घटनाओं को रोके, विशेष रूप से वह इस अशांत क्षेत्र के गांवों से सत्ताधारी दल के पार्टी कार्यकर्ताओं की लूटपाट करने वाले लुटेरों को हटाए।
२. ऐसे सभी प्रशासनिक उपाए किए जाएं जिससे सुरक्षा की भावना तथा लोगों का विश्वास बहाल हो सके।
३. प्रभावित क्षेत्र से राज्य पुलिस को हटाने का निर्देश दे और उसके स्थान पर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को लगाया जाए।
४. राज्य सरकार से कहा जाए कि वह भू-अधिग्रहण अधिसूचना को वापस ले तथा लोगों को पक्का विश्वास दिलाए कि इस क्षेत्र में किसानों की किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा।
५. पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दें कि वह नंदीग्राम में इस खास प्रयोजन से एक विशेष थाना बनाए जिसमें एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस तथा सीपीएम कार्यकर्ताओं के अत्याचारों, बलात्कार के आरोपों, गायब लोगों की रिपोर्टों और अन्य ऐसी शिकायतों की रिपोर्टों को दर्ज करे।
६. इस विशेष पुलिस चौकी की विशेष रूप से हिदायत दी जाए कि वह सीपीएम की स्थानीय समिति की लिखित अनुमति प्राप्त लिए बिना सभी शिकायतों को दर्ज करे क्योंकि यह दुःख की बात है कि पश्चिम बंगाल के अनेक भागों में समिति की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है।
७. मृतकों तथा घायल लोगों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजे का वितरण किया जाए।

राष्ट्रपतिजी, पूरा देश साधारण, बेआवाज लोगों के साथ आपकी सहानुभूति की सराहना कर रहा है। वे तो अब आपसे इस विषय में आपकी प्रेरणा और मदद की बाट जोह रहे हैं। नंदीग्राम के लोग अब फिर से आपका आश्वासन, पीड़ा पर आपकी मरहम लगाने की प्रतीक्षा में है, जिससे उन पर हुए जुल्मों को समाप्त किया जा सके। हमारी आपसे अपील है कि आप

यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र अपने समय में से कुछ घण्टे निकाल कर इन प्रभावित गांवों का दौरा करें और डरे हुए इन लोगों को सांत्वना दें। इससे उनके जीवन को कुछ शान्ति मिलेगी और मौजूदा व्यवस्था में विश्वास पैदा होगा जिसने उनके साथ गहरा अत्याचार किया है। हमें विश्वास है कि आप हमारी इस अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

■

सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक....

यूं तो पिछले 30 साल से माकपा शासित पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और वामपंथियों ने बड़ी चतुराईपूर्वक इससे देशभर के नागरिकों से बेखबर रखा। आतंक, भय और दमन का पर्याय बनी माकपा ने पुलिस और प्रशासन को अपने कब्जे में कर लिया और अपने मंसूबे को अंजाम देने लगी। लेकिन गत वर्ष से वाममोर्चा सरकार के चेहरे से नकाब उतरना शुरू हो गया है। पिछले नवम्बर में सरकार ने सिंगूर में लखटकिया कार प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन हथिया ली। किसानों द्वारा इसका प्रतिरोध करने पर माकपा के गुण्डों और पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। माकपा शासन का किसान विरोधी चेहरा सार्वजनिक तौर पर उजागर हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इससे सबक नहीं लिया उलटे किसानों की भूमि का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर जारी है। हम यहां सिंगूर की घटना पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं:—

सिंगूर में पुलिसिया कहर

किसानों की जमीन को लूटा, फिर पीटा

देशभर में पानी पी-पी कर पूंजीपतियों को कोसने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पश्चिम बंगाल में शर्मनाक तरीके से पूंजीपतियों का पिटठू बन कर किसानों पर जुल्म ढा रही हैं। माकपा शासित पश्चिम बंगाल में किसान, मजदूर और समाज के पिछड़े लोगों का बुरा हाल है। माकपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। किसानों और मजदूरों के हितों का राग अलापने वाली माकपा के एजेण्डे में केवल पूंजीपतियों और अमीरों का

हित संवर्द्धन है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने सिंगूर में टाटा मोटर्स को छोटी कार परियोजना के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन दे दी है। इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किसानों ने संघर्ष छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार के इशारे पर पुलिस ने गरीब किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया।

वामपंथी सरकार के दमन के शिकार हुए किसानों के हित को लेकर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्हें सिंगूर जाते समय हुगली के डानकुनी थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित माइतीपाड़ा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार बनर्जी, महासचिव राहुल सिन्हा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी गिरफ्तार हुए। इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ४ दिसम्बर से तृणमूल के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सुश्री बनर्जी ने राज्य की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए उसे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वह धरना स्थल से नहीं हटेंगी और इस आन्दोलन को उग्र किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और तृणमूल के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एकजुटता जाहिर करते हुए पश्चिम बंगाल की किसान विरोधी वाममोर्चा सरकार की जमकर आलोचना की।

किसानों पर जुल्म ढा रही है वाम मोर्चा सरकार: राजनाथ सिंह

भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा सिंगूर के किसानों के साथ किए जा रहे ज्यादती पर प्रहार करते हुए कहा कि यही समय है कि राज्य की जनता वाममोर्चा सरकार के चरित्र को समझ ले। जो सरकार साधारण जनता की हितैषी होने का दंभ भरती है वही उद्योगपतियों के हित के लिए साधारण कश्षकों की जमीन अधिग्रहण कर रही है।

उन्होंने कहा कि सिंगूर में दो और तीन फसली जमीन है। इस जमीन का उपयोग कल कारखाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं टाटा से अपील कर रहा हूं कि किसानों और गरीबों की खून की कीमत पर कारखाना न लगायें। उन्होंने पं. बंगाल की वाममोर्चा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार खुद ही 'ग्रीन रेवेल्यूशन' की बात कर रही है

जबकि कितना विरोधाभास है कि वही सरकार आज किसानों की जमीन उद्योगपतियों को दे रही हैं। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां गेहूं और दाल का आयात किया जाता है। अगर उपजाऊ जमीन भी निकल गयी तो फिर खाद्यान्न संकट को कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकश्ष्ट किया कि मजदूरों की हिमायत करने वाली राज्य की माकपा नेतृत्व वाली सरकार में अनेक उद्योग बंद पड़े हैं लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही और उल्टा किसानों पर अन्याय, अत्याचार की घटनायें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि राज्य में उद्योगों का विकास होना चाहिए लेकिन कृषि जमीन पर नहीं, बल्कि बंजर या अनुपयोगी जमीन का उपयोग किया जाये। उन्होंने कहा कि ममता इस संघर्ष में अकेली नहीं है भाजपा उसके साथ है और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और संसद से सड़क तक तृणमूल पार्टी के साथ मिलकर जमीन अधिग्रहण का विरोध जारी रहेगा।

संसद में गूंजा किसानों पर अत्याचार का मामला

भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ४ दिसम्बर को हुई पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की गिरफ्तारी के विरोध तथा उनकी रिहाई की मांग को लेकर राज्यसभा में जमकर शोरशराबा और हंगामा किया। भाजपा के सांसदों ने पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी की।

लोकतंत्र विरोधी माकपा सरकार

मार्क्सवादी सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। सिंगूर में किसान अपने खेत को बचाने के लिए विरोध-प्रदर्शन तक नहीं कर सकता। क्षेत्र में टाटा मोटर्स की परियोजना के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के विरोध और सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सिंगूर में धारा १४४ लगा दी है। सिंगूर के रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

भाजपा ने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन

सिंगूर मामले पर पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्यपाल से पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप की मांग की गई। श्री राय ने कहा कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की जिद के कारण सिंगूर में किसानों व उनके परिजन पर पुलिस अत्याचार कर रही है। ■

रिपोर्ट : नंदीग्राम नरसंहार

मार्क्सवादियों ने दोहराया जालियांवाला बाग कांड

अपना हक मांग रहे किसानों पर तड़ातड़ बरसती गोलियां..... गरीब किसानों के खून से लाल हुई धरती..... खेतों में पड़ी अनगिनत लाशें लहुलुहान बच्चे और औरतें अस्पतालों में दम तोड़ते गरीब लोग..... .... चारों ओर तबाही का मंजर..... यही आलम है माकपा शासित राज्य पश्चिम बंगाल का..... इतिहास मार्क्सवादियों को कभी माफ नहीं करेगा।

नंदीग्राम में माकपा का खूनी चेहरा एकबार फिर उजागर हुआ। जिनके हितों का झूठी दंभ भरकर ये सत्ता हथियाते है इन दिनों माकपा इन्हीं मजदूर-गरीब किसानों को गोलियों से भूनने में जुटी हुई हैं। किसानों का कसूर केवल इतना ही है कि वे अपना हक मांग रहे है।

ग़ौरतलब है कि कि नंदीग्राम में इंडोनेशियाई औद्योगिक घराने सलीम समूह के प्रस्तावित रासायनिक कारखानों के लिए भू-अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। वामपंथी सरकार ने इस संयंत्र की स्थापना के लिए इस गाँव की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपनी ज़मीन पर ऐसी कोई इकाई नहीं चाहते हैं और उन्हें उनकी ज़मीनें वापस कर दी जाएँ।

१४ मार्च, २००७ को नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाम मोर्चा सरकार के इशारे पर पुलिस ने जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें कम से कम २० लोग मारे गए और २०० से अधिक घायल हो गए। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा सहित अनेक संगठनों ने इस घटना के विरोध में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस्तीफे की मांग को लेकर १६ मार्च को १२ घंटे के राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया, जो ऐतिहासिक रुप से सफल रहा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ६ सदस्यीय दल ने १७ मार्च २००७ को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने के बाद घटनास्थल का जायजा

लिया।

इसके बाद नंदीग्राम के पास सोनाचुरा बाजार में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि यहां उद्योग धंधों को बसाने का विरोध कर रहे किसानों पर १४ मार्च को जो भी हुआ, उसने जालियावालां बाग हत्याकांड को भी पीछे छोड़ दिया।

श्री आडवाणी ने कहा कि जालियावालां बाग कांड तो अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ था लेकिन आजादी के पांच दशक बाद नंदीग्राम में यह जनसंहार हुआ। मार्क्सवादियों पर बरसते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि नंदीग्राम जनसंहार के लिए इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। इस दल में राजग के संयोजक जार्ज फर्नांडीस राज्यसभा में भाजपा की उपनेता सुषमा स्वराज, एस.एस. आहलुवालिया सहित ६ वरिष्ठ सांसद भी शामिल थे।

नंदीग्राम नरसंहार को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के ख़िलाफ़ नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बैनर्जी ने सरकार को बर्खास्त करने की माँग की है।

विकास के नाम पर किसानों की भूमि न छीनें- राष्ट्रपति कलाम

नंदीग्राम नरसंहार को लेकर राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने भी पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार की कड़ी आलोचना की है। राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने १७ मार्च २००४ को कहा कि देश के पालनहार किसान पर हमले नहीं किए जाने चाहिए और न ही उनकी उपजाऊ जमीन को कब्जे में लिया जाना चाहिए। यदि उद्योग लगाना ही है तो बंजर भूमि पर लगाए जाने चाहिए।

डा. कलाम ने कहा कि इस बाबत आपसी सहमति होनी चाहिए। किसानों के खिलाफ किसी तरह का बल प्रयोग या फिर आर्थिक विकास के नाम पर उनकी भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर उसे उद्योगों को सौंपने का काम नहीं होना चाहिए। कलाम ने कहा कि भूमि दो तरह की है- कृषि योग्य और बंजर। उद्योगों को बंजर भूमि में लगाना चाहिए जो किसान के उपयोग में नहीं आती।

उन्होने जोर दिया कि सरकार को उद्योगों के गठन से पहले किसानों से विचार विमर्श करना चाहिए। हालांकि उन्होंने याद दिलाया कि इस दिशा में समस्याएं हमेशा ही रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के गठन का समर्थन करने वाले राष्ट्रपति का यह बयान उस समय आया है जब पश्चिम बंगाल में

नंदीग्राम में उग्र ग्रामीणों पर पुलिस फायरिंग की घटना में १४ लोग मारे गए थे और अनेक घायल हो गए थे।

प. बंगाल में धारा ३५५ का इस्तेमाल हो : आडवाणीजी

लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने केन्द्र सरकार से नंदीग्राम पुलिस गोलीबारी मामले में संविधान के अनुच्छेद ३५५ का इस्तेमाल कर पश्चिम बंगाल की वामदलों की सरकार को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देने और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने की मांग की है। श्री आडवाणी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से फोन पर बात की और उन्होंने प्रधानमंत्री से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इस घटना की रिपोर्ट मांगने के लिए पहल करने का आग्रह किया।

उन्होंने नंदीग्राम गोलीबारी को पश्चिम बंगाल की वामदलों की सरकार और उसके कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस की मदद से की गई बर्बर हिंसा की कार्रवाई बताया। केन्द्र सरकार से की गई सात सूत्री मांग में उन्होंने नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के निर्माण के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने और वहां अर्द्धसैनिक बल भेजने की मांग की जिसका वहां के किसान विरोध कर रहे हैं।

श्री आडवाणी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने बुद्धदेव सरकार को घटना से दो दिन पहले ही आगाह कर दिया था। श्री गांधी ने इस घटना को भयाक्रांत करने की सुनियोजित योजना करार दिया है। यह पहला मौका है जब किसी राज्य के प्रमुख ने राज्य सरकार के खिलाफ इतने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री आडवाणी ने नंदीग्राम फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की तुरंत घोषणा करने और नंदीग्राम की भयभीत जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने की मांग की।

पश्चिम बंगाल में अलोकतांत्रिक सरकार : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने नंदीग्राम में हुए पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत और सैकड़ों की संख्या में घायल होने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस घटना के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनकी सीपीएम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। श्री सिंह ने इस घटना की न्यायिक या संसदीय जांच कराने की मांग भी की।

श्री सिंह ने कहा कि गत ३ माह से नंदीग्राम एवं सिंगूर में हो रही पुलिस फायरिंग पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में ही दो बड़ी घटनाओं में कई लोगों की जानें जा चुकी है। यहां हो रही लगातार

घटनाओं से यह बात साफ हो गई है कि यहां के हालात पश्चिम बंगाल की सरकार के हाथ से निकल चुके हैं। निरीह किसानों पर निरंतर फायरिंग, लाठीचार्ज करते रहना वामपंथी सरकार के असली चहरे को उजागर करता है।

श्री सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी हो चुकी है। वह किसानों से बातचीत के बजाए अब उन पर गोली एवं लाठी बरसाने का काम कर रही है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को नैतिक आधार पर क्षणभर भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि एक तरफ नंदीग्राम पुलिस फायरिंग में किसान मारे जा रहे थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधानसभा में औद्योगिकरण की आड़ में सिंगूर टाटा प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहे थे। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है।

श्री सिंह ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का एक शिष्टमंडल नंदीग्राम जाएगा और वहां पुलिस फायरिंग में मारे गए एवं घायल परिवारों से भेंट कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौपेंगे।

सरकार सदन चलाने की इच्छुक नहीं : सुषमा स्वराज

भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि राजग की बैठक में इस बात पर अफसोस जताया गया कि सरकार की ओर से सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इसके बाद उन्होंने प्रियरंजन दासमुंशी को फोन करके पूछा कि संयुक्त संसदीय दल भेजने के बारे में क्या फैसला किया गया है। दासमुंशी ने उन्हें बताया कि मैंने पूरा रिकार्ड देख लिया है। पहले कभी भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ऐसा दल नहीं भेजा गया। दूसरी बात यह है कि इस फायरिंग के संबंध में अदालत का फैसला आ गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए आमराय जरूरी है जो कि इस मामले में नहीं है।

श्रीमती स्वराज ने इसके जवाब में कहा कि अगर नरसंहार को कानून व व्यवस्था की बात कहते हो तो बातचीत का आधार ही समाप्त हो जाता है। जहां राज्यपाल अपनी वेदना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर रहा हो। हाईकोर्ट खुद संज्ञान ले रहा हो उसे कानून व व्यवस्था का मामला नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका व प्रेस, लोकतंत्र के स्तंभ हैं। इनमें से तीन अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। जबकि विधायिका की तो पहली जिम्देारी बनती है और जहां तक सर्वसम्मति का

सवाल है समूचा विपक्ष इस पर एकमत है। सिर्फ सरकार में ही सहमति नहीं है। घटक दलों में सहमति बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके जवाब में दासमुंशी ने इतना ही कहा कि मैं देखता हूं।

पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा की रिपोर्ट

राजग प्रतिनिधिमंडल का नंदीग्राम दौरा

वरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग के एक संसदीय प्रतिनिधि दल जिसमें श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री जार्ज फर्नांडीज शामिल थे, १७ मार्च को कलकत्ता से चलकर नंदीग्राम (सोनाचुड़ा) पहुंचा। जहां १४ मार्च को माकपाई कैडर एवं पुलिस द्वारा निर्ममतापूर्वक १४ (सरकारी आंकड़ा) लोगों की मृत्यु एवं १५० लोग घायल हुए थे। वहां इन सभी प्रतिनिधियों के गांव के लोगों ने उस दिन घटने वाली घटनाओं का विवरण सिलसिलेवार सुना। ५ वर्षीय शिशु की हत्या, १५ से ५० वर्षीय महिलाओं तक का बलात्कार पुलिस एवं कैडरों ने बारी-बारी से किया। एक ५० वर्षीय महिला के गर्भाशय में लोहे के छड़ घुसेड़ कर घायल किया गया ऐसे हृदय विदारक घटनाओं को सुनकर सारे प्रतिनिधि भावुक हो उठे। वहां एक सभा हुई जिसमें आडवाणीजी, सुषमाजी, आहलूवालियाजी एवं प्रदेश भाजपा नेता श्री राहुल सिन्हा ने भाषण दिया। आडवाणीजी ने इस घटना की तुलना जालियांवाला बाग से किया।

नंदीग्राम की पहली घटना ३ जनवरी को हुई थी। सबसे पहले प्रदेश भाजपा के नेता वहां ५ जनवरी को ही पहुंच गये। ठीक इसके बाद श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में १० जनवरी को भाजपा संसदीय दल पहुंचा और मौके का जायजा लिया। इस घटना के विरोध में भाजपा प्रदेश महामंत्री ने उच्च न्यायालय में एसएलपी दायर दिया कि एचडीए (हल्दिया डेवलपमेंट ऑथिरिटी) जिसने जमीन अधिग्रहण का नोटिस लगाया था वह गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एचडीए को कोई अधिकार नहीं है लेकिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री झूठे साबित हुए। ५ दिसंबर २००५ को राज्य सरकार ने एचडीए को जमीन अधिग्रहण करने का अधिकार सौंप दिया था। उच्च न्यायालय में बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया।

उच्च न्यायलय के निर्देश पर सीबीआई जांच के दौरान जिन १० लोगों को गिरफ्तार किया गया ये सभी बाहरी माकपाई गुंडे हैं यह प्रमाणित हो गया। ऐसी घटना यहां हमेशा होते रहते हैं पर इस बार बड़े असाधारण ढंग से कुकृत्य करने से एवं मीडिया के माध्यम से सारे लोगों को समझ आ गया

जिससे सीपीएम के चेहरे से नकाब उतर गया। हालांकि सीपीएम कैडर द्वारा ऐसा अत्याचार सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए ही किया जाता है।

नंदीग्राम में सौ से ज्यादा लापता

नंदीग्राम में पुलिस फ़ायरिंग की घटना के बाद से सौ से ज्यादा लोग लापता हैं। केंद्रीय जाँच एजेंसी यानी सीबीआई पुलिस फ़ायरिंग की घटना की जाँच कर रही है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि उन्हें लापता लोगों के बारे में उनके परिजनों से शिकायतें मिली हैं। जाँच एजेंसी स्थानीय प्रशासन और वहाँ रहने वाले लोगों की मदद से लापता व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

किसानों के संघर्ष की जीत- वाममोर्चा सरकार और यूपीए सरकार बैकफुट पर आई

नंदीग्राम की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने वहाँ भू-अधिग्रहण नहीं करने और प्रस्तावित एसईजेड नहीं बनाने का फ़ैसला किया है। उधर नंदीग्राम की घटना के बाद केन्द्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार भी बचाव की मुद्रा में गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जब तक भूमि अधिग्रहण की समस्या हल नहीं होगी तब तक किसी नए सेज को मंजूरी नहीं मिलेगी।

१००० माकपाइयों ने छोड़ी पार्टी

नंदीग्राम में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर फायरिंग की घटना से दुखी पश्चिम मेदिनीपुर जिले के झाड़ग्राम अनुमंडल में लगभग एक हजार माकपाइयों ने पार्टी छोड़ अपने गुस्से का इजहार किया।

नंदीग्राम में फायरिंग जायज : बुद्धदेव

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, कुख्यात तानाशाह स्टालिन के नए अवतार साबित हो रहे हैं। श्री भट्टाचार्य ने निर्लज्ज तरीके से नंदीग्राम में हुई पुलिस गोलीबारी को जायज ठहराया है।

नंदीग्राम में जो हुआ सीएम से पूछ कर: गृह सचिव

राज्य के गृह सचिव प्रसादरंजन राय ने २१ मार्च को यह बताया कि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री बुद्धदेव को थी। वह सब कुछ जानते थे। नंदीग्राम में पुलिस व प्रशासन ने जो कुछ किया, उन्हें बता कर ही किया।

गृह सचिव ने कहा कि नंदीग्राम में १४ मार्च की सुबह पुलिस की तैनाती की गई थी। इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को थी। इतना ही नहीं, खुफिया रिपोर्टों के आधार पर उसके बाद की कार्रवाई की जानकारी भी भट्टाचार्य को दी गयी थी। गत २० मार्च को राज्य सरकार द्वारा नंदीग्राम की घटनाओं

की सीआईडी जांच के लिए दिए गए आदेश के बारे में गश्ह सचिव ने कहा कि यह कदम सीबीआई की ओर से खेजुरी थाने में १० लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई एक एफआईआर के आधार पर उठाया गया हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त १० लोगों की गिरफ्तारी एक ईंट-भट्ठे के पास से की गई थी। इनके पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे।

वामपंथियों पर मीडिया भी बरसी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के इशारे पर राज्य की पुलिस एवं माकपा के कैडरों द्वारा नंदीग्राम के किसानों पर ढाए गए जुल्म को देश के सभी समाचार पत्रों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और तथाकथित किसान मजदूर की हितैषी वाम मोर्चा सरकार की पोल खोल दी है। हम यहां राष्ट्रीय समाचार पत्रों की संपादकीय लेखों व महत्वपूर्ण समाचार के प्रमुख अंश को प्रकाशित कर रहे हैं:–

जनसत्ता

नंदीग्राम का सबक

बुधवार का दिन वाममोर्चा के शासन का सबसे काला दिन साबित हुआ। ज्यादा दुखद बात यह है कि पुलिस के साथ-साथ माकपा कार्यकर्ताओं ने भी ग्रामीणों पर हमला बोला। यहां तक कि पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। अगर मान लिया जाए कि उकसावे की घटना पहले भीड़ की तरफ से हुई तो भी इतने बड़े पैमाने पर की गई पुलिस फायरिंग को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ही कहा जा सकता है। लिहाजा, नंदीग्राम में हुए गोलीकांड को कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश भर नहीं माना जा सकता। इस घटना की जवाबदेही से माकपा और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पल्ला नहीं झाड़ सकते।

दैनिक भास्कर

संक्रमण काल का संग्राम

पश्चिम बंगाल सरकारी नीतियों और संघर्ष के सिद्धांत का संक्रमणकालीन द्वंद्व झेल रहा है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाद, विवाद और संवाद को प्रस्थापना देता है। लेकिन सिंगुर से लेकर नंदीग्राम तक द्वंद्व में सिर्फ वाद, विवाद दिख रहे हैं, संवाद नदारद है। एक तरफ अपनी जमीन बचाने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाने वाले किसान व बटाईदार हैं तो दूसरी ओर हर

हाल में परियोजना पूरी करने की गर्वोन्नत घोषणा कर रहे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। ऐसी स्थिति में कभी हिंसा भड़क जाती है और कुछ लोग मारे या घायल हो जाते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। नंदीग्राम की ताजा हिंसा इस बात का सबूत है कि उस इलाके के लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है।

हिन्दुस्तान

दमन नहीं, दिल जीतें

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को नहीं लगता कि पुलिस ने नंदीग्राम में कुछ गलत किया है। कुछ लोगों को हैरत हो सकती है कि किसानों और ग्रामीणों पर पुलिस की गोलीबारी की किसी वारदात के बाद दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जैसे बयान देते हैं, वैसा ही बयान उस सरकार का मुख्यमंत्री दे रहा है, जो मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों को सत्ता देने का दंभ भरती थी। प्रदेश के विकास की रणनीति तैयार करना अगर सरकार का काम है तो अपने हितों से टकराव होने पर उसका विरोध करना लोगों का मूल अधिकार है। लोकतंत्र में विकास की पैसेंजर गाड़ी इन्हीं रास्तों से सरकार और विपक्ष सभी के धैर्य की परीक्षा लेते हुए धीरे-धीरे गुजरती है। बुद्धदेव की दिक्कत यह है कि उन्होंने यह रास्ता पुलिस की ताकत के बल पर बनाने की कोशिश की और नतीजा वही हुआ, जो ऐसी कोशिशों का होता है।

दैनिक जागरण

लाशों की सेज

गांव, गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों की बात बढ़-चढ़ कर करने वाले वामदलों के गढ़ पश्चिम बंगाल में पुलिस के हाथों १४ ग्रामीणों की मौत स्तब्ध करने वाली है। यह दुखद है कि नंदीग्राम में लाशों का ढेर लग जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को इस बात का अहसास हुआ कि सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना उस तरह नहीं होनी चाहिए जैसे कि उनकी सरकार करने की कोशिश कर रही थी। क्या बुद्धदेव यह बताएंगे कि यदि नंदीग्राम में जमीन का अधिग्रहण रोक दिया गया था तो फिर वे कौन से कारण थे जिनके चलते स्थानीय लोगों ने विरोध जारी रखने की जरूरत महसूस की? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह नंदीग्राम में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन और बचाव कर रहे हैं।

नवभारत टाइम्स

खूनी मोड़

नंदीग्राम में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। इसमें कई लोगों को न

सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी है, बल्कि सेज (स्पेशल इकानॉमिक जोन) को लेकर पहले से जारी बहस और भी उलझ गई है। बंगाल की सीपीएम सरकार के लिए इसका अंजाम जो भी हो, पूरे देश के लिए यह एक बुरा मोड़ है। सेज के मुद्दे को यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। वह नहीं पहुंचता अगर बंगाल सरकार ने थोड़ी अक्लमंदी दिखाई होती। यह प्रशासनिक भूल से बड़ा मामला है। यह एक आपराधिक गड़बड़ी है, जिसका नतीजा बदकिस्मती से सभी को झेलना पड़ेगा।

अमर उजाला

नंदीग्राम में खूनी खेल

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जो खूनी खेल खेला गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम होगी।

विधानसभा में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नंदीग्राम में पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया है। अव्वल तो ऐसी बर्बरता को जायज ठहराना ही अमानवीयता है। सरकार का तर्क है कि नंदीग्राम में बीते ढाई महीने से कानून का राज नहीं था। यानी हिंसक माकपा कार्यकर्ताओं को इलाके से खदेड़ देने से कानून-व्यवस्था ठप्प हो गई थी। वाम मोर्चे के राज में इससे पहले कई बार विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की गई, गांव के गांव जला दिए गए, तब कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं उठता था। लिहाजा खूनी हिंसा को जायज ठहराने वाले मुख्यमंत्री से कुछ सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए।

मसलन, जब नंदीग्राम में अभियान पहले से तय था और यह भी मालूम था कि आंदोलनकारी चुप बैठे नहीं रहेंगे, तब यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि जनहानि न हो? कानून-व्यवस्था बहाल करने की ऐसी कोशिश को किस तरह जायज ठहराएंगे जिसमें चौदह लोगों की जान गई? पुलिस फायरिंग में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्ची भी थी। सरकार को जवाब देना चाहिए कि कानून-व्यवस्था को उस मासूम से क्या खतरा था। शुक्र है कि माकपा की असलियत खुद उसके सहयोगियों के सामने आ गई है। फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने तो इस घटना की निंदा की ही है, भाकपा महासचिव का कहना है कि करीब तीस साल के वाम मोर्चे शासनकाल में ऐसी घटना कभी देखी नहीं गई। राज्यपाल भी इस बर्बरता पर टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके, जबकि सांविधानिक पद पर बैठे आदमी को सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देकर ठीक किया है। किसानों के बल पर राज करने वाली माकपा किसानों को निशाना बनाकर

सत्ता से तो जाएगी ही, लेकिन इससे पहले उसकी कथित नैतिकता का मुलम्मा उतरना जरूरी है।

दैनिक ट्रिब्यून

बुद्धदेव के माथे का कलंक

पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा नंदीग्राम में स्थानीय लोगों पर गोलियां चलाये जाने के कारण १४ ग्रामीणों की मौत के बाद एक राजनीतिक नेत्री ने इसकी तुलना जलियावाला बाग से की है। टीवी पर निहत्थी महिलाओं और बच्चों को लाठीचार्ज द्वारा पीटे जाने के दृश्य तथा मरने वालों में अनेक महिलाएं और बच्चे शामिल होने के समाचारों के चलते पुलिस पर बर्बरता के आरोप गलत नहीं लगते। पुलिस की गोलियों से लगभग २०० लोगों के घायल होने तथा पत्रकारों को नंदीग्राम जाने से वामदलों के कार्यकर्ताओं द्वारा रोके जाने के समय की गयी टिप्पणियां देखें तो यह नहीं लगता कि सरकार या सत्ताधारी गठबंधन संयत व्यवहार का कायल है। इस घटनाक्रम के बाद जारी वक्तव्यों से यह लगना स्वाभाविक है कि वाममोर्चा तथा इसका नेतृत्व कर रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नंदीग्राम के लोगों पर अत्याचार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने नंदीग्राम में ५००० पुलिसकर्मियों के भेजे हाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या यह बर्बरता तथा हिंसा अनावश्यक नहीं है?

देश के वामपंथी राजनेता अन्य दलों की नीतियों की आलोचना करने तथा उन्हें उपदेश देने के मौके कभी नहीं चूकते पर नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, उससे स्पष्ट है कि 'जन पक्ष की राजनीति' करने का दावा उनकी करनी के उलट है।

पंजाब केसरी

नंदीग्राम में भड़की असंतोष की आग

नंदीग्राम में १४ मार्च को जो कुछ हुआ है उसने लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या उद्योगों व सेज की स्थापना के लिए मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण किए जाने पर किसान इसी प्रकार मरते रहेंगे। आखिर किसानों के इस प्रकार मारे जाने से उन परियोजनाओं की क्या पावनता रह जाएगी।

पश्चिम बंगाल सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसी परियोजना जिसके विरोध में इतने लोगों का खून बह रहा है वह उसे श्रेय दिलाने की बजाय उसकी छवि को कलंकित ही करेगी।

प्रमुख समाचार

हाईकोर्ट का कड़ा रुख सीबीआई जांच के आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम में पुलिसिया जुल्म को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को घटना की जांच के लिए तत्काल एक टीम नंदीग्राम भेजने की हिदायत दी। कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ग्रामीणों की मौत के लिए प्रथम दृष्ट्या सरकार को दोषी माना है। चीफ जस्टिस एसएस निज्जर और जस्टिस पीसी घोष की डिवीजन बेंच ने नेशनल एलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट और कुछ वकीलों की याचिका पर यह आदेश दिया।

नंदीग्राम में बाहरी लोगों ने चलाई थी गोलियां!

नंदीग्राम में बेगुनाह ग्रामीणों पर पुलिस फायरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार चाहे यह सफाई दे रही हो कि हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी, लेकिन जांच में यह साफ होता जा रहा है कि 'बाहरी सशस्त्र' लोगों ने ग्रामीणों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया था। शक की सुई सबसे ज्यादा माकपा कार्यकर्ताओं की ओर घूम रही है।

सीबीआई की टीम ने दो दिन पहले नंदीग्राम में एक ईंट भट्टे पर छापा मार कर १० लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किए गए थे। सीबीआई की टीम के एक अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर खुलासा किया कि आरोपियों में से कोई भी नंदीग्राम का नहीं है। सभी लोग बाहर से वहां आए हुए थे।

जांच अधिकारियों को फायरिंग के स्थान से बड़ी संख्या में ऐसी गोलियों के खोल मिले हैं जिनका इस्तेमाल सामान्यतः पुलिस नहीं करती। ऐसी गोलियों को देशी हथियारों में प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि फायरिंग बाहरी लोगों ने की।

माकपा कार्यकर्ताओं पर शक क्यों

- गिरफ्तार लोगों में माकपा नेता नारू मेती भी है। उसके पिता देबाशीष मेती ने भी इसकी पुष्टि की है।
- देबाशीष हालांकि इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि उनका बेटा फायरिंग में शामिल है, लेकिन उनका कहना है कि यदि उन्हें नारू की योजना की जानकारी होती तो वे उसे नंदीग्राम नहीं जाने देते।
- देबीशेष ने खुलासा किया है कि नारू के साथ गिरतार अन्य लोग भी माकपा कार्यकर्ता हैं।
- एक प्रत्यक्षदर्शी ने खुलासा किया है कि फायरिंग करते वक्त एक पुलिस वाला जूते की बजाय चप्पल पहने था।
- कुछ पुलिसकर्मियों ने मुंह भी ढक रखे थे। यदि पुलिसकर्मियों ने मुंह भी ढक रखे थे। यदि पुलिसकर्मियों को फायरिंग के आदेश थे तो उन्हें चेहरा छिपाने की क्या जरूरत थी।

नंदीग्राम पर फंस गए करात

माकपा महासचिव प्रकाश करात यह तो कह रहे हैं कि नंदीग्राम में फ्री फॉर ऑल की स्थिति है, लेकिन वे इस सवाल का जवाब देने के इच्छुक नहीं हैं कि इस तरह की स्थिति बनने देने के लिए क्या कहीं उनकी अपनी बुद्धदेव सरकार भी दोषी है। करात ने नंदीग्राम के ब्लाक-१ की स्थिति बयान करते समय कहा कि वहां न शासन है और न पुलिस। माकपा के कार्यकर्ता भी वहां से भगा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा वहां केवल तृणमूल कांग्रेस और नक्सलवादी हैं, लेकिन लाख पूछे जाने पर भी करात यह बताने को तैयार नहीं हैं कि इसका अर्थ यह माना जाए कि राज्य सरकार वहां असफल हो गई।

करात से सीधा सवाल हुआ कि राज्य के किसी भी इलाके में अगर कानून का शासन ध्वस्त होता है तो क्या इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर नहीं आती। करात का उत्तर था कि नंदीग्राम में हथियारबंद लोगों ने एक तरह से कब्जा कर रखा था। सवाल हुआ कौन थे वे लोग? उनका उत्तर था- अब सीबीआई को यह पता लगाना होगा। उन्होंने नंदीग्राम की घटना पर गहरा खेद तो जताया, लेकिन राज्य सरकार की आलोचना करने वाले सहयोगी वामदलों के बयानों सहित हर बयान को खारिज कर दिया। हालांकि करात कोलकाता में ही यह बयान दे चुके हैं कि नंदीग्राम की घटना के आलोक में मुख्यमंत्री बदले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सहयोगी दलों के तीखे तेवरों पर करात की सफाई थी- हां, यह ठीक है कि कई चीजों पर उन्हें नाराजगी थी पर अब वे मसले सुलझा लिए गए हैं। करात ने फिर वही दावा किया जिसे पहले ही आरएसपी झूठा करार दे चुके हैं। करात ने कहा कि नंदीग्राम में पुलिस भेजे जाने का फैसला सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया था।

जमात-ए-उलेमा हिंद के प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठियां

नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग और हिंसा पश्चिम बंगाल सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही। नंदीग्राम कांड के खिलाफ आयोजित रैली के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय राईट्र्स बिल्डिंग की ओर मार्च कर रहे धार्मिक संगठन जमात-ए-उलेमा हिंद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मध्य कोलकाता में जमकर लाठियां बरसाई। जमात-ए-उलेमा हिंद ने इस रैली का आयोजन नंदीग्राम में १४ लोगों की मौत और जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किया था। पुलिस ने कहा कि धर्माताला में रैली करने के बाद राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यह कार्रवाई करनी पड़ी। लाठीचार्ज में चार पत्रकारों के साथ-साथ भारी संख्या में उलेमा के कार्यकर्ता जख्मी हो गए। दोनों तरफ से पथराव में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए।

नंदीग्राम में दहशत और आतंक: राज्यपाल

राज्यपाल ने नंदीग्राम की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उसे टाला जा सकता था। उन्होंने तमलक अस्पताल में घायलों को देख कर कहा-मैं यहां घायलों से मिलकर मर्माहत हूं। उन्हें समुचित चिकित्सा भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। नंदीग्राम में राज्यपाल को भी आगे जाने से रोका गया।

बुद्धिजीवियों का धिक्कार दिवस

बुद्धिजीवियों ने कोलकाता में धिक्कार जुलुस निकाला और मुख्यमंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। इस जुलुस की अगुवाई महाश्वेता देवी, गौतम घोष, सांवली मित्र, नवनीता देवसेन, जया मित्र, विभा, चक्रवर्ती, रूद्र प्रसाद सेनगुप्त जय गोस्वामी कर रहे थे।

मसले पर संघर्ष जारी रहेगा : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम मामले पर संसद में औपचारिक चर्चा नहीं कराए जाने पर सरकार की तीव्र भर्त्सना करते हुए संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है। राज्य सभा में पार्टी की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने २० मार्च २००७ को नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री आडवाणी लोकसभा में नन्दीग्राम मामले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे पर अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण यह मामला उठा था जिसके चलते हत्याकाण्ड हुआ। अतः केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस पर संसद में चर्चा कराये। उन्होंने कहा कि संप्रग के घटक दल बिखरे हुए हैं और कई प्रश्नों को लेकर उनमें मतभेद हैं। भाजपा नहीं चाहती कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें एकजुट होने का मौका दिया जाए और सरकार की प्रशंसा में भाषण हो। ■

कम्युनिस्टों की दादागीरी के आगे बेबस कांग्रेस

नंदीग्राम की घटना ने कम्युनिस्टों की थोथी क्रांतिकारिता की कलई खोल दी है। खुद को संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरूआ बताने वाले कम्युनिस्टों का दोहरा चेहरा खुलकर सामने आ गया है। नंदीग्राम में आम जनता के विरूद्ध राजसत्ता की आतंकी कार्रवाई के बाद अब वामपंथी इस मुद्दे पर संसद को भी गूंगा कर देना चाहते हैं। कम्युनिस्टों के तेवर तो ऐसे हैं कि अगर बस चले तो वे संसद में 'नंदीग्राम' शब्द पर ही प्रतिबंध लगा दें।

कम्युनिस्टों की दादागीरी के आगे कांग्रेस भी बेबस है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी है कि *'जबरा मारे और रोने भी न दे।'* नंदीग्राम का दौरा कर लौटा कांग्रेस का तीन सदस्यीय दल भी मान रहा है कि नंदीग्राम की हिंसा में पुलिस के साथ माकपा के काडरों ने भी खूनी खेल खेला, जिसमें तीन कांग्रेस कार्यकर्ता भी मारे गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिग्विजय सिंह, मोहसिना किदवई और मधुसूदन मिस्त्री ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म व बच्चों के विरूद्ध बर्बर कार्रवाई की बातें स्वीकार की हैं।

इसके बावजूद केन्द्रीय सत्ता बचाने की मजबूरी ने सरकार के हाथ बांध दिए हैं। माकपा के दबाव के चलते सरकार संसद में राजसत्ता के इस बर्बर कश्त्य पर चर्चा के लिए राजी नहीं हो रही। माकपा का बहाना भी क्या खूब है! कहा जा रहा है कि मामला राज्य सरकार का है, लिहाजा संसद में चर्चा नहीं हो सकती।

इस पूरे मामले में कांग्रेस की लाचारी की बानगी सिंघवी के इस बयान में झलकती है। उनका कहना था कि 'जो हुआ वह काफी निंदनीय और गंभीर है, लेकिन राज्य सरकार के इस्तीफे का मामला हम नैतिकता पर छोड़ते हैं।' विडंबना यह है कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल से कांग्रेसी सांसद और मंत्री भी वामपंथियों की दादागीरी का बखान कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप खून का घूंट पीने को मजबूर हैं।

उधर, वामपंथियों की हेकड़ी का क्या कहना? सदन में विपक्ष के यह मामला उठाने की कोशिश करते ही वह ऐसा आसमान सिर पर उठा रहे हैं कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के पास सदन स्थगित करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। नतीजतन, वित्त विधेयक समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के सदन के पटल में रखने की औपचारिकता हुई। कई सदस्यों को इसका दर्द भी है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर व

राज्यसभा सदस्य विमल जालान ने अपनी इस पीड़ा को बयान भी किया।

उन्होंने कहा कि 'कौन सा विधेयक पारित हुआ यह तक नहीं पता चल पाता। ऐसे में सदन का मतलब क्या?' विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाने के पक्ष में कई वाजिब तर्क दे रहा है। दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष इस विषय में चर्चा के लिए नोटिस भी दे रहे हैं, लेकिन वामपंथियों के लाल-पीले तेवरों के चलते यह मामला संसद में सिर्फ एक तकनीकी आधार पर नहीं उठाने दिया जा रहा। इसीलिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लालकश्ष्ण आडवाणी को सदन में कहना ही पड़ गया कि 'नंदीग्राम में राज्य के आतंकवाद और पुलिस की बर्बरता को केन्द्र सरकार रोकने में विफल रही है। अब सदन में भी कम्युनिस्टों का यह आतंकवाद दिखाई दे रहा है।' नेता प्रतिपक्ष की यह टिप्पणी बिल्कुल असंगत भी नहीं है।

एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले पर यह बवाल हुआ तो इस मामले से केन्द्र खुद को अलग कैसे कर सकती है? इतना ही नहीं, वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के विरोध का झंडा उठाए रहने वाले वामपंथी पश्चिम बंगाल के बारे में इन मुद्दों को भूल गए हैं। उनकी हालत धूमल की कविता की तरह ठीक वैसे ही है कि दिखावे के लिए 'मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी दबी रहे।' यही नहीं अब वामपंथी इसे राज्य सरकार का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन गुड़गांव में होंडा कंपनी के मजदूरों पर लाठीचार्ज के मामले पर माकपा और भाकपा में ससंद को ठप कराने की होड़ लगी थी। दोनों ही सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और भर्त्सना भी हुई। राजस्थान के घरसाणा में किसानों पर गोलीबारी का मामला भी संसद में उठा।

मगर अब जब अपने सरकार के कारनामे पर चर्चा की बात आई तो कम्युनिस्ट बेहद हास्यास्पद तर्क देकर इस मुद्दे को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी की बात पर गौर फरमाएं तो भी यही पुष्ट होता है। नंदीग्राम पर गतिरोध के चलते लोकसभा एक दिन पहले ही २६ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुंशी के मुताबिक यह प्रस्ताव भी भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता ने ही दिया था।

साभार (दै. जागरण) ■

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख

माकपा का मुखौटा नंदीग्राम के आईने में

& egk'osrk nsoh

मैं वृद्ध हो गई हूं। न जाने कब चल बसूं। लेकिन चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद योद्धा की मेरी पहचान रह जाए। मैंने जीवनभर कोई युद्ध किया है, तो मुख्यतः कलम से। कलम ही मेरा हथियार है और ८२ वर्ष की उम्र में मुझे अंतिम भरोसा अपने हथियार पर ही है। कलम के इस हथियार से आज भी युद्ध किए जा रही हूं। इसी के साथ नृशंसता का प्रतिवाद भी यथासाध्य कर रही हूं, सड़क पर उतर कर। पहले भी किया है और जब तक जीवित रहूंगी, करती रहूंगी। नंदीग्राम में बुद्धदेव भट्टाचार्य की असामान्य 'कीर्ति' के विरूद्ध अभी हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। इस प्रसंग पर मैं बाद में आती हूं। पहले बुद्धदेव की असामान्य 'कीर्ति' पर।

स्त्रियों की इस त्रासदी और नंदीग्राम के नरसंहार के लिए बुद्धदेव जिम्मेदार है। वे हत्यारे हैं। नंदीग्राम के लिए आज एक ही शत्रु हैं और वह है बुद्धदेव सरकार।

बुद्धदेव अत्याचारी हैं, मानवाधिकार विरोधी हैं। क्या अपनी पुलिस और अपने कैडर से इतने लोगों की हत्या कराने के बाद भी बुद्धदेव मुख्यमंत्री बने रहेंगे?

क्या आपने टीवी पर नंदीग्राम में १४ मार्च को बुद्धदेव भट्टाचार्य की 'कीर्ति' को नहीं देखा? मैंने देखा। पूरे बंगाल ने देखा। बुद्धदेव ने १९१९ के जलियांवाला बाग के डायर साहब को भी लज्जित कर दिया। माकपा की गुंडावाहिनी ने इस शताब्दी का एक नया इतिहास नंदीग्राम में लिखा। नंदीग्राम आज का जलियांवाला बाग है। नंदीग्राम ने मां, बहनों, भाइयों और पतियों के रक्त से स्नान किया है। टीवी चैनल पर महिलाओं और बच्चों पर गोली चलाने का

दृश्य हम सबने देखा है। निरीह और निःशस्त्र महिलाओं, बच्चों, किशोरों और किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। यह फायरिंग हत्या के उद्देश्य से की गई, क्योंकि घायलों और मृतकों के पेट, गले, छाती में गोलियां लगी हैं। कई लोगों को काटकर भी मार डाला गया। हताहतों की संख्या सरकारी आंकड़े से बहुत ज्यादा है। नंदीग्राम में नरसंहार के बाद कई लाशें गायब कर दी गईं। नंदीग्राम में पुलिस को रोकने के लिए वहां के आम नागरिकों ने गढ्ढे खोद कर रास्ते काट डाले थे। नरसंहार के बाद उन गढ्ढों में लाशें डाल कर ऊपर से कंक्रीट और सीमेंट से उसे पाट डाला गया। कई लाशें नदी या नहरों में या दूर जंगल में ले जाकर फेंक दी गईं। यह सारा कृत्य पुलिस और माकपा कैडरों ने मिलकर किया। नरसंहार के बाद कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कुछ स्त्री-पुरूषों के जननांग में गोली मार दी गई। वे नित्य क्रियाएं भी नहीं कर पा रहे हैं। क्षत-विक्षत जननांग लेकर क्या ये स्त्री-पुरूष सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे? स्त्रियों की इस त्रासदी और नंदीग्राम के नरसंहार के लिए बुद्धदेव जिम्मेदार है। वे हत्यारे हैं। नंदीग्राम के लिए आज एक ही शत्रु हैं और वह है बुद्धदेव सरकार।

बुद्धदेव अत्याचारी हैं, मानवाधिकार विरोधी हैं। क्या अपनी पुलिस और अपने कैडर से इतने लोगों की हत्या कराने के बाद भी बुद्धदेव मुख्यमंत्री बने रहेंगे? प्रकाश करात ने कोलकाता आकर फैसला सुनाया- हां, बने रहेंगे। बंगाल माकपा के लोग मेधा पाटकर को बाहरी कहते हैं। मैं पूछती हूं कि जब मेधा बाहरी हैं तो करात बाहरी नहीं है? माकपा की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य विनय कोंगार ने पिछले महीने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मेधा पाटकर बाहरी हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मेधा और ममता नंदीग्राम जाएंगी, तो वहां के माकपा समर्थक उन्हें अपना 'पाछा' दिखाएंगे। नंदीग्राम नरसंहार के पहले मेधा पाटकर जब नंदीग्राम गई थीं, तो वहां विनय कोंगार की घोषणा के मुताबिक माकपा के कैडरों ने अपना पैंट खोलकर दिखाया था। नरसंहार के बाद मेधा जब गईं, तब कोई अभद्रता नहीं हो सकी, क्योंकि सीबीआई की टीम नंदीग्राम में मौजूद थी। नरसंहार के दिन जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के करीब पहुंची, तो उनकी गाड़ी रोककर माकपा के कैडरों ने अभद्र नारे लगाए और उन्हें वापस कोलकाता जाने को कहा। ममता दूसरे दिन नंदीग्राम पहुंच सकी थीं।

मैं दिल्ली और भारत के अन्यान्य इलाकों के वामपंथी बुद्धिजीवियों से पूछना चाहती हूं कि वे नंदीग्राम के नरसंहार और महिलाओं पर अत्याचार पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी राय में नंदीग्राम भारत में है या इराक में? नंदीग्राम में नरसंहार के विरूद्ध कोलकाता हाईकोर्ट व बंगाल की अन्य अदालतों के वकील स्वतः स्फूर्त ढंग से सड़क पर उतरे। वामपंथी माने

जाने वाले बुद्धिजीवी लेखक, कलाकार भी सड़क पर उतरे। नरसंहार के दूसरे दिन ही धर्मतला में लेखकों, कलाकारें ने धिक्कार जुलू निकाला। ऐसा ही धिक्कार जुलूस १७ मार्च को भी कॉलेज स्क्वॉयर में निकला, जिसमें अपर्णा सेन, गौतम घोष, मनोज मित्र, विभास चक्रवर्ती, रूद्रप्रसाद सेनगुप्त, जया मित्र, सांली मित्र, जय गोस्वामी, नवारूण भट्टाचार्य, कबीर सुमन, प्रतूल मुखोपाध्याय, शुभा प्रसन्न समेत एक हजार से ज्यादा लेखकों, शिल्पियों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया।

मैंने अस्वस्थ होने के बावजूद दोनों जुलूसों में हिस्सेदारी की। लेखकों की दो सभाओं में भी मैं गई। इसके अलावा १६ मार्च को धर्मताला में आयोजित जमाए-ए-उलेमाए-हिन्द की सभा में भी मैंने भाषण किया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा- मैं जीवन की सांध्यबेला में भी बुद्धदेव भट्टाचार्य की बर्बरता के विरूद्ध युद्ध किए जा रही हूं। नंदीग्राम के नरसंहार का प्रतिवाद किए जा रही हूं और जनतंत्र में आस्था रखनेवाले सभी लोगों से उम्मीद करती हूं कि वे भी मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारे लगाएंगे बुद्धदेव सरकार, और नहीं दरकार, नंदीग्राम में जिन निर्दोष लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी शहादत से प्रेरणा ग्रहण कर सिंगुर, हरिपुर बारूईपुर, बारासात और राजारहाट के लोग भी जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध और ताकत के साथ युद्ध छेड़ेंगे।

मैं पहले सिंगुर गई थी। यह युद्ध भी स्वाधीनता संग्राम जैसा ही है। यह लक्ष्यपूर्ति तक चलता रहेगा। सरकार का कहना है कि नंदीग्राम में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए वहां पुलिस गई। यह सरासर झूठ है। तथ्य यह है कि नंदीग्राम के लोग सशस्त्र नहीं थे। इसे टीवी चैनल ने दिखाया है। सशस्त्र थे माकपा के समर्थक। उन्हें एक माकपा सांसद ने हथियार उपलब्ध कराए थे। यह कहना भी गलत है कि नंदीग्राम में पुलिस नहीं जा पा रही थी। खेजुरी से तो नंदीग्राम में सब कुछ आ रहा था। खेजुरी में बैठकर ही माकपा के नेताओं ने नंदीग्राम की कार्रवाई का ब्लू प्रिंट तैयार किया था। उसे ब्लू प्रिंट के अनुसार सुनियोजित तरीके से एक अफवाह फैलाई गई कि नंदीग्राम के माकपा समर्थक काकली गिरी के साथ जमीन उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के लोगों ने बलात्कार किया। इस अफवाह के बाद ही स्थिति को नियंत्रण में करने के नाम पर पुलिस कार्रवाई का फैसला किया गया, लेकिन कार्रवाई के ठीक पहले काकली गिरी एक चैनल पर आई और उन्होंने खुलासा किया कि यह उनके खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है कि उनके साथ बलात्कार हुआ। काकली ने माकपा को बेनकाब कर दिया। मुझे उम्मीद हे कि सीबीआई भी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और माकपा का मुख और मुखैटा एक बार फिर देश देखेगा। ■

अब सीपीएम को शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है

& pUnu fe=k

जब-जब मुझे बचपन में पढ़ी रबिन्द्रनाथ टेगौर के साहित्य की याद आती है, तब-तब मुझे लगता है कि वे कितने भविष्यदृष्टा थे उनके साहित्य में उनकी सार्वलौकिक धारणा के दर्शन होते है। यह सचमुच अद्वितीय है कि ८० वर्ष पूर्व अपने प्रचुर सृजन साहित्य के कारण पहले नोबल पुरस्कार विजेता बनकर उन्होंने अपनी कविताओं तथा साहित्यिक अंशों में ऐसा कुछ लिखा जो चिरंतन काल तक बना रहेगा। उदाहरण के लिए उनकी लघु कविता 'दोई बीघा जोमी' को ही लें। इसमें दो बीघा जमीन के स्वामित्व वाले गरीब किसान की पीड़ा भरी पड़ी है। एक दिन, एक स्थानीय जमीदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस गरीब आदमी का घरबार छीन कर उसे गांव से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। बहुत वर्षों बाद, वह इस गांव में अपने घर वापस लौटा और अपने घर की याद में पीड़ित उस जमीन के छोटे से टुकड़े को देखा जो कभी उसका था।

यह एक साधारण किसान और उसके भूखण्ड के बीच भावात्मकता एकता थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। अपनी याद में डूबते हुए वह उस आम के पेड़ के साये में सो गया, जिसे उसने बहुत पहले लगाया था। इन तमाम वर्षों में वह आम का पौधा बड़ा हो गया और उस समय वह बड़ा पेड़ आमों से भरा हुआ था। अपनी यादों में खोए उस पेड़ से दो आम उसके पास उसके प्यार को देखते हुए आ गिरे। अभी वह बेचारा किसान इन आमों को कुदरत की देन समझ कर अश्रुपूर्ण निगाहों से स्वीकार कर ही रहा था कि तभी उस जमींदार के पहलवान वहां आ गए और उस पर अपने मालिक के फल चुराने का आरोप लगा दिया। उसे घसीट कर जमींदार के पास ले जाया गया जहां गुस्से से भरे मुसाहिबों ने खूब गालियां दी और उस गरीब किसान पर शर्मनाक चोरी का इल्जाम लगा कर अपमानित किया। उस शक्तिशाली आदमी ने जिसने उसकी थोड़ी सी दो बीघा जमीन छीन ली थी, उसने इतनी भी पहचान नहीं की कि यही तो उस जमीन का मालिक था। उसे इन आमों की चोरी के लिए जबरदस्त चेतावनी देते हुए बाहर निकाल दिया गया तो उस किसान को अपने ऊपर बड़ा अफसोस होने लगाः

''आज के जमाने में वही सबसे बड़ा लालची है, जिसके पास सब कुछ है। राजा की तो प्रकृति ही यह है कि गरीब के पास जो कुछ भी है, सब कुछ छीन लो....

क्या विडम्बना है? जहां जमींदार को ईमानदार माना जा रहा है वहां आज मुझे चोर समझा जा रहा हैं।''

आज यही बात सीपीआई (एम) की श्रमजीवियों के साथ तानाशाही में हो रहा है। श्रमजीवियों को भू-माफियों का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि तानाशाहों के राज में अपने विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए सब कुछ सही माना जाता है। आज तथाकथित कम्युनिस्ट बाहर से आए गैर-बंगाली धनवानों, भवन निर्माताओं और लंगोटिया पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ कर बड़ी बेदर्दी से घरेलू और विदेशी उद्योगपतियों के लाभ के लिए राज्य की उपजाऊ जमीन छीन रहे हैं। यदि सिंगूर घटना के बाद पूर्वी मेदनीपुर के नंदीग्राम में किसान लोग विद्रोह पर उतर आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है?

आज तथाकथित कम्युनिस्ट बाहर से आए गैर-बंगाली धनवानों, भवन निर्माताओं और लंगोटिया पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ कर बड़ी बेदर्दी से घरेलू और विदेशी उद्योगपतियों के लाभ के लिए राज्य की उपजाऊ जमीन छीन रहे हैं। यदि सिंगूर घटना के बाद पूर्वी मेदनीपुर के नंदीग्राम में किसान लोग विद्रोह पर उतर आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है?

पहले ही मालूम था कि सीपीएम को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है, वह किसी भी प्रकार की आलोचना को धृष्टतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार है। कारण यह है कि कम्युनिस्टों की सदैव यही प्रतिक्रिया रहती है क्योंकि उनका तो मानना है कि सच वही है जिसे वह मानते हैं। कम्युनिस्टों की डिक्शनरी में आत्मचिंतन करने जैसा कोई शब्द ही नहीं है। यही कारण है कि रात भर में द्वितीय विश्व-युद्ध का नक्शा बदल गया। यह स्टालिन-रिबेनट्राप पैक्ट के दौरान एक ''साम्राज्यवादी युद्ध'' था, जब मास्को ने चुपचाप हिटलर की लूटमार करने वाली फौजों का साथ दिया, यहुदियों के दमन पर चुप्पी साध रखी और अपने सहयोगी देशों की हार का मजा लिया। जब चालाक हिटलर ने समझौता तोड़ा और समाजवादी देशों पर हमला कर दिया तब युद्ध को ''पीपुल्स वार'' में बदल कर इसे 'लोकतंत्र' की रक्षा का रूप दे दिया। इस प्रकार, 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भारतीय

कम्युनिस्टों ने खुले आम औपनिवेशिक खुफिया एजेंसियों के लिए कांग्रेस के खिलाफ 'इंफार्मर' का काम किया।

पुरानी कहावत है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, उनकी आज के संदर्भ में भी उतनी ही निंदा होती रहती है। एक तरफ कांग्रेस ने नंदीग्राम घटना को 'नरसंहार' बताया है और राष्ट्रपति शासन की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी हाइ कमान को सीपीएम से इतना भी कहने की हिम्मत नहीं है कि वह बंगाल में कानून-व्यवस्था बहाल करे।

रक्तरंजित बुधवार (१४ मार्च) की काली करतूतों के बारे में सीपीएम जिस तरह से बचाव कर रही है वह तो दुरभि संधि का एक मजेदार नमूना है, मैंने उन्हें पिछले सोमवार को संसद के सेन्ट्रल हाल में पत्रकारों से बहस करते सुना कि देश को तो बुद्धदेव सरकार का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने भारत के लिए नंदीग्राम को बचा लिया। उनके गलत तर्कों के आधार पर इस क्षेत्र पर तो नक्सलवादी कब्जा कर लेते, आप मानें या न माने इस पर 'मुस्लिम कट्टरवादी' कब्जा कर लेते। समझा जाता है, वामपंथियों और दक्षिणपंथी अतिवादियों के बीच सरकार के सभी प्राधिकारों का गांवों के एक समूह से नामोनिशान तक मिट गया था। समझा जाता है कि जमायत उलेमा-ए-हिंद के नेतृत्व में मुल्लाओं में परिवार-नियोजन और पल्स पोलियों अभियान को सफल न होने देने की बात कही, जबकि नक्सलवादी चे-ग्वेरा स्टाइल तैयार करने की कोशिश में थे।

इसलिए सीपीएम कैडर के प्रेरणादायी, मार्गनिर्देशन में ''पश्चिम बंगाल देशभक्त पुलिस' मार्क्स-लेनिन-बुद्धदेव विचारों में लीन होकर नंदीग्राम की एकता के भव्य मिशन को पूरा करने के लिए खतरनाक राष्ट्रविरोधी ताकतों की गोलियों का सामना करने लगे। इसी प्रक्रिया में लगभग २० लोग मारे गए, अपने लोग घायल हुए, पत्रकारों को घेरेबंदी वाले क्षेत्र से बाहर रखने को मजबूर किया- यह सब कुछ उस स्थिति में जैसे अपरिहार्य क्षति थी। जो बात नहीं कही गई, वह यह थी कि उस भूमि पर 'पुन कब्जा' करना अनिवार्य हो गया था, जिसे इण्डोनेशिया सलेम ग्रुप को गिरवी रख दिया गया था ताकि वह हल्दिया बंदरगाह के पास आसानी से 'कैमिकल हब' बना सके। उन्हें पहले कोलकाता के नजदीक काफी बड़ी कृषि भूमि का आवंटन कर दिया गया था, जहां पर 'अर्जुन' नाम से दो पहिए महाभारत स्कूटर का निर्माण होना था, जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना है। आज जब बजाज स्कूटर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूटर बन रहा है तो कोई समझदार व्यक्ति क्यों अर्जुन खरीदेगा? हां, जब तक कि पार्टी अपने हर सदस्य को यह निर्देश न दे कि उसे 'रेड' सलेम का सेल्समैन बनना है, जो निश्चित ही एक संभावना हो सकती है।

छिछोरेपन के अलावा, सिंगूर-नंदीग्राम विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में लगभग तीन-चौथाई बहुमत वाली सीपीएम को अब शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। लगभग एक दशक पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैंने 'मॉरल एकानामी आफ दि पीजेण्ट'' जावा, इण्डोनेशिया के किसानों के संदर्भ में पुस्तक पढी थी। उसके लेखक ने ग्रामीण समाज में उस समय चल रही स्थिति के सही और गलत का बड़ा अच्छा चित्रण किया था। इतिहासकार और समाजशास्त्री न होने पर भी महात्मा गांधी ने किसानों की नैतिकता को बड़े अच्छे ढंग से समझा था। यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी ताकत का सफलतापूर्वक सामना किया। जब किसी सरकार के पास शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है, जैसा कि पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्टों का शासन नहीं रहा, तो चाहे जितना जोर लगा लें, वे एकजुट नहीं रह सकते हैं। मार्को फिलीपींस और ईरान में रजा शाह पहलवी की दक्षिणपंथी तानाशाही भी उसी तरह आखिरकार विफल हो गई।

गोलियों से भले ही लोगों को चुप करा दें, परन्तु उसका स्वरूप अस्थायी रहता है। मौन रूप से बंगाल को अवश्य ही जलियांवाला बाग पर रबिन्द्रनाथ द्वारा ईश्वर से किए वे प्रश्न याद आते होंगे, जो उन्होंने आक्रोश में किए थेः

''मेरी आवाज अवरूद्ध हो गई है, अब मेरी बंसी बज नही पा रही है, आज जेल जैसा अंधेरा लगता है जैसे कि बिना चांद की रात हो। मेरा विश्व भयानक रात में खो गया हैं। इसलिए मैं अपनी आंखों में आंसू भरकर पूछता हूंः आपने जो वातावरण तैयार किया था, उसमें किसने जहर घोला, किसने आपके जलाए दीए को बुझाया- क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? क्या आप उन्हें प्यार करते हो?

(हिन्दी अनुवाद)

(लेखक 'पायनियर' के सम्पादक तथा राज्यसभा के सदस्य हैं)■

माकपा के माथे पर कलंक

& Loiunkl x|r

नंदीग्राम में माकपा कार्यकर्ताओं के इशारे पर पुलिस ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघते हुए कम से कम १४ निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया और सैकड़ों को घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इस घटना से पश्चिम बंगाल में तीन दशक से शासन कर रही माकपा के माथे पर कलंक लगने के साथ ही उसका दमनकारी चेहरा भी सामने आ गया है। इस भयानक हादसे से यह जाहिर हो गई है कि सत्ता के नशे में चूर दल न तो आलोचना बर्दाश्त कर सकते हैं और न ही विपक्ष की दलीलें। नंदीग्राम में जो हुआ उसकी वजह यह नहीं थी कि राज्य सरकार विकास के लिए कृतसंकल्प थी बल्कि इसके पीछे बाहुबल का प्रदर्शन करने की सोच थी। पिछले तीस सालों में सूबे के ग्रामीण इलाकों में माकपा का एकछत्र राज है। गांवों में माकपा की पैठ का मतलब यह नहीं कि लाल झंडा जनता के दिल में बसता है। माकपा ने अपनी पकड़ भोली-भाली जनता को डरा-धमका कर बनाई है।

१९७७ से बंगाल में सत्ता सुख भोग रही माकपा ने ग्रामीणों को दो वर्गो में विभाजित कर दिया है। एक तो वे जो उसके साथ हैं और दूसरे वे जो साथ नहीं है। सीमावर्ती जिलों को छोड़कर समूचे ग्रामीण बंगाल में माकपा की गहरी पकड़ का राज अब खुलने लगा है। माकपा ने क्रूरता और आतंक के बल पर गांवों में अपना जो साम्राज्य स्थापित किया है उससे मुक्ति के लिए अब बड़ी संख्या में स्थानीय समुदाय आवाज बुलंद करने लगा है। माकपा सरकार ने स्टालिनवाद पर न केवल उपदेश दिए बल्कि राज्य में पूरी निर्लज्जता के साथ उसे पाला पोसा। इसकी आड़ में माकपा रहनुमा की खाल ओढ़कर किसी क्रूर राजा की तरह तानाशाही का साम्राज्य फैलाती रही। नंदीग्राम को लेकर बौद्धिक किस्म के कुछ लोग वामपंथी सरकार की आलोचना करने का पाखंड कर रहे हैं। ऐसे लोग कपटी हैं। कई दशकों तक वामपंथियों ने जब अपने विरोधियों को कुचलने के लिए दमनकारी रवैया अपनाया तब यही बौद्धिक लोग उनके साथ थे और उनकी नीतियों का

गुणगान करते थे। बंगाल को रक्तरंजित बनाने में इन लोगों का भी उतना ही दोष है जितना वामपंथियों का। ऐसे लोग वामपंथियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र का भी हिस्सा रहे हैं। अब वे अपना दामन पाक साफ दिखाने के लिए वाम सरकार को भला-बुरा कह रहे हैं। नंदीग्राम की हिंसा से माकपा के चेहरे से नकाब उतार गया है और उसकी असली सूरत पूरे देश के सामने आ गई है। अब जब भी सहमत द्वारा बनाई गई फिल्म को गुजरात में वितरक न मिलें और उसे लेकर वामपंथी न्याय की दुहाई दें या फिर जब भी संसद के बाहर बृंदा कारत आदिवासियों के साथ फोटो सेशन कराती दिखें या फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य सूफियाना लहजे में नेरुदा या ब्रेख्त की कविताओं का पाठ करते दिखें तब उनके द्वारा ढहाए गए जुल्मों की याद दिलाने के लिए एक ही शब्द काफी होगा-नंदीग्राम। नंदीग्राम की हिंसा वाम आंदोलन के रक्तरंजित इतिहास की न तो पहली घटना है और न ही आखिरी। १९१७ की बोलशेविक क्रांति के दौरान हुए खूनखराबे और वाम आंदोलनों में कई फर्क नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत के संदर्भ में नंदीग्राम की घटना अहंकार में चूर ऐसे लोगों के लिए मील का पत्थर बन गई है जिन्होंने ताल ठोककर घोषित कर दिया है कि इतिहास ने एक बार फिर उनके पक्ष मे करवट ली है। नंदीग्राम की हिंसा के बाद माकपा जहां बचाव की मुद्रा में आ गई है वहीं कांग्रेस नेतृत्व का दोहरा चरित्र भी उजागर हो गया है। सोनिया गांधी की मजबूरी है कि वह भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हाथों मारे गए ५५ जवानों की हत्या पर हायतौबा नहीं मचा सकतीं क्योंकि फिर उन्हें नंदीग्राम पर भी कुछ बोलना पड़ेगा। नंदीग्राम को लेकर कांग्रेस आंख पर पट्टी बांधकर और कान में रुई डालकर बैठी है क्योंकि संप्रग सरकार वामपंथियों की बैसाखी पर ही टिकी हुई है। वामपंथी विचारधारा का बौद्धिक समुदाय खामोश है। उनमें से बहुतों की आंखों का पानी मर चुका है। उनकी अंतरात्मा वामपंथी सत्ता तले मर चुकी है। देशभर में गंभीर होते जा रहे खाद्यान्न संकट को देखते हुए विशेष आर्थिक जोन पर चल रही बहस ने अब राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। यह बहस आक्रामक नहीं है लिहाजा संप्रग

जब भी संसद के बाहर बृंदा कारत आदिवासियों के साथ फोटो सेशन कराती दिखें या फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य सूफियाना लहजे में नेरुदा या ब्रेख्त की कविताओं का पाठ करते दिखें तब उनके द्वारा ढहाए गए जुल्मों की याद दिलाने के लिए एक ही शब्द काफी होगा-नंदीग्राम।

सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पडेग़ा। हालांकि राजग इस मामले को धार देने में जुटा है। मेधा पाटेकर और मुसलिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन भले ही वक्त के साथ कमजोर पड़ जाएं लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह साल पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली के बीच उड़ान शुरू होने की ४०वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। माकपा के समर्थन से सत्ता में आई यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने खूनखराबे की शुरुआत की जिसे नक्सली आंदोलन और कांग्रेस की गुंडागर्दी ने आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं कि इस वजह से आर्थिक प्रगति की राह में पश्चिम बंगाल पिछड़ता गया।

क्या आपको १९६७ का घेराव आंदोलन याद है तब हुबली नदी के दोनों किनारों पर स्थित हजारों फैक्ट्रियां खाली हो गईं थीं। इस आंदोलन से वाम राजनीति पर प्रतिकूल असर पड़ा और उनकी बहुत आलोचना हुई थी। पश्चिम बंगाल का पतन केवल आर्थिक रूप से ही नहीं हो रहा। वामपंथियों के अजीबोगरीब राजनीतिक कदमों की वजह से इस राज्य ने सामाजिक रूप से भी बहुत कुछ खो दिया है। एक ब्रिटिश टिप्पणीकार ने किसी दूसरे संदर्भ में दुख और हताशा से भरे समुदाय का जिक्र किया था जो आज के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल पर बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आपको यकीन न हो तो मृणाल सेन और रित्विक घटक की फिल्में देख लीजिए आपकी आंखें और सोच दोनों खुल जाएंगे। अनाचार और कमियां अब सिर्फ वामदलों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि गैर-वाम दल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। नंदीग्राम की घटना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों से यह बात जाहिर भी हो गई है। ■

वामपंथ का दोहरा चरित्र और खूनी खेल

& Mk- jkdi'k fl Ugk

किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए राजनीतिक विश्लेषण में असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह मेरी मान्यता रही है। परन्तु पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के द्वारा जिस बर्बरता, क्रूरता एवं राक्षसी वृत्ति का प्रदर्शन हो रहा है, उसे देख कर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सत्ता में उसके तीन सहयोगी पिछलग्गुओं (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फारवर्ड ब्लॉक), के लिए 'दोगले' जैसे शब्द का प्रयोग भी, उनका सम्मान करने जैसा लगने लगा है। १५ मार्च को नंदीग्राम में एक दर्जन से अधिक गरीब-मजदूर-किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार उनकी जमीन, जमीर और जान का मुआवजा देकर 'सेज' संवारने में लगी हुई है। सिंगुर और नंदीग्राम में लगातार हिंसा का तांडव हो रहा है। किसानों-मजदूरों का हक क्या है यह जानने का एकाधिकार तो कम्युनिस्टों ने अपने लिए सुरक्षित रखा हैं। वे अपने आप को सर्वहारा का सिपाही कहते रहे हैं। उन्हीं के नाम पर राजनीति की रोटी सेंकते रहे हैं और जब सर्वहारा वर्ग अपने न्यूनतम अधिकारों के लिए संघर्ष पर उतरने लगा तब कम्युनिस्ट शासन ने असली चाल, चेहरा और चरित्र दिखा दिया।

बुद्धदेव भट्टाचार्य या उनकी पार्टी के लिए नैतिकता की बात करना मूर्खता होगी। इसलिए यह अपेक्षा करना कि इतने गरीब किसानों की मौत के बाद बुद्धदेव इस्तीफा दे देंगे, दोपहर की धूप में आसमान में तारे खोजने के समान होगा। संभवतः कम्युनिस्टों से कहीं अधिक संवेदनशीलता तो टाटा और सलेम ग्रुप में होगी। उनसे एक बार तो अपेक्षा की जा सकती है कि वे एक कदम पीछे हट जाएं और मजदूर-किसानों के खून से सनी धरती पर कार कारखाना या सेज का निर्माण नहीं करें। लेकिन राज्य के कम्युनिस्ट शासन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती।

माकपा में आज बुद्धदेव के खिलाफ बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। किसान सभा, सीटू, एसएफआई जैसे संगठनों की जबान हिल तो रही है लेकिन इन खूनी कारनामों का औचित्य साबित करने के लिए। मजदूरों की

रोजी-रोटी छीनने और उन पर हिंसात्मक कार्रवाई में भी ये क्रांति के दर्शन कर रहे हैं। मजदूरों- किसानों की बात करते हुए शहीद हुए सफदर हाशमी की याद में बना 'सहमत' जैसा संगठन भी मौन धारण किए हुए है। सीपीआई संगठनात्मक रूप से पूरी तरह विकलांग है। इसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। देश के सभी प्रांतों में 'अजय भवनों' के अतिरिक्त इसके पास कुछ नहीं बचा है- माकपा, कांग्रेस और लालू यादव जैसी बैसाखियों और मीडिया की सहानुभूति की बदौलत इसका राजनीतिक अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है। इसलिए माकपा से असहमति जताते हुए भी यह वाम मोर्चे में बनी हुई है। और सबका एक ही रक्षा कवच है- 'हिन्दू साम्प्रदायिकता का खतरा'। आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक अपनी औकात जानते हैं, इसलिए उनके पास 'बुद्धम शरणम गच्छामि' के सिवा कोई चारा नहीं है।

इस पूरे प्रकरण में यह अहम सवाल उभरता है कि आखिर सीपीएम का चरित्र क्या है? सीपीएम का जन्म सीपीआई में विभाजन के परिणामस्वरूप १९६४ में हुआ था। सीपीआई की राष्ट्रीय परिषद के ३२ सदस्यों ने भारत-चीन युद्ध पर पार्टी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को प्रतिक्रियावादी और बुर्जुआ नेतृत्व के साथ समझौता करार दिया था। सीपीआई का मानना था कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ये ३२ सदस्य, जिन्होंने सीपीएम का गठन किया, मानते थे कि माओ का नेतृत्व भारत के लिए अनुकरणीय है। वे भारत को ही भारत-चीन युद्ध के लिए दोषी मानते थे। सीपीआई के दस्तावेज (बैटल अगेंस्ट माओइज्म एंड नक्सलिज्म) में लिखा गया है- यह सीपीआई से माओवाद के प्रभाव में टूट कर अलग हुई है। और इसी का अनुकरण करते हुए अपने कैडर को माओवाद की महानता स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया है। इसी दस्तावेज में आगे कहा गया है कि सीपीएम ने सांस्कशतिक क्रांति (१९६७) के दौरान लोगों पर हुए अत्याचार को भी सही ठहराया है। माओ के उत्तराधिकारों ने सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुई बर्बरता के लिए माओ को अपराधी माना, लेकिन सीपीएम की माओभक्ति बनी रही। यह अकेली घटना नहीं है। सोवियत संघ में स्टालिन ने १९२९ से १९५३ तक जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसे सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टालिन के बाद के सोवियत नेतृत्व ने भी अपने मूल्यांकन में स्टालिन को दोषी माना, परन्तु सीपीएम को यह अच्छा नहीं लगा। आखिर बर्बरता के बिना मार्क्सवाद क्या! इसलिए उसने मद्रास कांग्रेस (१९९२) में जारी पार्टी के दस्तावेज- ऑन सर्टेन आइडियोलॉजिकल इश्यूज, में सोवियत कम्युनिस्ट नेताओं को स्टालिन के गलत मूल्यांकन के लिए दुत्कारा। उसमें लिखा है- सीपीएम व्यक्तिवाद को ठीक करने के नाम पर अपनाए गए दृष्टिकोण को अस्वीकृत करती है। यह समाजवाद के इतिहास को निषेध है। लेनिनवाद के पक्ष, ट्राटस्कीवाद और अन्य सैद्धांतिक

भटकाव के विरूद्ध स्टालिन के निर्विवाद योगदान को इतिहास के पन्नों से नहीं मिटाया जा सकता। तीसरी घटना है चीन के थ्येनआनमन चौक पर नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को सरकार द्वारा बर्बरता से कुचल देने को भी सीपीएम समाजवाद की रक्षा के लिए उचित और साहसी कदम मानती रही है।

जिस पार्टी ने अपने जन्म से ही बर्बरता को वर्ग-संघर्ष मान लिया हो, उसका चाल, चेहरा, चरित्र कैसा होगा? सत्ता के लिए सीपीएम किसी तरह का समझौता कर सकती है। इसके लिए गांधीवाद से लेकर स्टालिनवाद और सोनिया गांधी से लेकर मुलायम सिंह तक सभी विकल्प खुले रहते हैं।

नंदीग्राम में जो हुआ वह पहली और अपवादस्वरूप घटना नहीं है। सीपीआई के ही वर्ग संघर्ष के प्रशिक्षण से नक्सलवाद का जन्म हुआ। सत्ता मिलते ही सीपीएम नक्सलवाद को अवैध वामपंथी संतान मानने लगी। सीपीआई के मुखपत्र 'न्यू एज' के १५ मई १९७७ के अंक में एक आलेख छपा- 'सीपीम करेंट पोस्चर' इसमें कहा गया है 'पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने कार्रवाई दल बनाया है, जिसमें समाज विरोधी तत्वों को शामिल किया गया है। इसने सीपीआई और अन्य वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं पर हिंसक आक्रमण किया और उन्हें मौत के घाटा उतारा। नक्सलवादी जो सीपीएम से अलग हुए, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। केरल में भी सीपीएम ने अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए हिंसा और लोगों पर आक्रमण का सहारा लिया।'

कम्युनिस्टों से अपेक्षा की जाती है कि वे सर्वहारा के प्रति संवेदनशील होंगे। परन्तु यह संवेदनशीलता तो उनके बीच जीने और मरने में होती है। सीपीएम वाले बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से देशभर में उन्होंने कितनी बार मजदूर-किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया है? इसके कितने कामरेड जेल गए हैं? सच तो यह है कि सीपीएम नेता सामूहिक रूप से एक ही बार जेल गए और वह भारत-चीन युद्ध के समय चीन की तरफदारी करते हुए भारतीय राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी के आरोप में।आज सीपीएम नेतृत्व सर्वहारा को छोड़कर कारपोरेट व व्यावसायिक घरानों का सिपाही हो गया है। यह विडंबना नहीं, चरित्र है। सर्वहारा विरोधी चरित्र और स्टालिनवादी चाल, माओवादी धूर्तता के साथ सीपीएम अपने नए पूंजीवादी दोस्तों के साथ रंग की नहीं खून की होली खेलने में जनहित देख रही है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और संघ संस्थापक हेडगेवार के जीवनीकार हैं)■

सरकार की आंखों पर सत्ता की पट्टी

& jktho çrki :Mh

नंदीग्राम की घटना देश और दुनिया की नजरों में वामपंथी सरकार के दमन का प्रतीक बन गई है।

पंद्रह निरीह लोगों की पुलिस की गोली से हत्या, कई लापता और २०० से अधिक निरीह किसान, महिला एवं बच्चों के घायल होने की सूचना, वह भी पश्चिम बंगाल के बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक दो दिन पहले राज्य द्वारा की गई हिंसा की मिसाल बनी। पश्चिम बंगाल सरकार ने चार हजार से अधिक सशस्त्र बल जो इंसास और कलाश्निकोव जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, किसानों के तथाकथित मोर्चे को तोड़ने के लिए भेजा।

पुलिस कार्रवाई के बाद वामपंथी सरकार ने बयान दिया कि मारे गए लोग उग्र थे और आत्मरक्षा में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। इनके वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने यह भी बयान दिया कि नंदीग्राम को माओवादियों की घेराबंदी से निकालने के लिए यह कठोर कदम उठाना पड़ा। शुरू के दौर में वामपंथी नेतृत्व द्वारा जोर-शोर से इस बात को देश में फैलाने का प्रयास किया गया कि माओवादियों से निपटने के लिए पुलिस एवं सरकार को यह अवांछित कदम उठाना पड़ा। यदि यह सत्य था तो यह आम अनुभव है कि देशभर में माओवादियों से लड़ने के लिए राज्य पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों का भी सहयोग लिया जाता रहा है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय रिर्जव पुलिस बल के अलावा सीमा सशस्त्र सुरक्षा बल की भी टुकड़ियां उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया। यदि माओवादियों की घेराबंदी थी तो मार्क्सवादी सांसद तरित तोपदार ने यह क्यों कहा कि पुलिस गोलाबारी अवांछित थी? इतना ही नहीं पथ निर्माण मंत्री सुभाष चक्रवर्ती ने पुलिस की कार्रवाई रोकने की मांग भी की थी। आरएसपी के सार्वजनिक कार्य विभाग के मंत्री सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए इस्तीफा तक देने की बात कह रहे थे। राज्य सरकार को समर्थन देने वाले सीपीआई, आरएसपी एवं फारवर्ड ब्लॉक जैसे सहयोगी दलों ने सरकार की इस पुलिसिया कार्रवाई के फैसले को एकपक्षीय और मनमाना बताकर इसकी भर्त्सना करते हुए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने तक की चेतावनी दी, परंतु एक बात जो इस

संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इन सहयोगी दलों में से किसी ने भी माओवादियों के साथ संघर्ष की चर्चा नहीं की। इन तथ्यों से सरकार और उनके वरिष्ठ नेताओं का यह कहना कि माओवादियों से लड़ने के लिए यह कार्रवाई की गई, सार्वजनिक झूठ निकला।

भाजपा ने वामपंथी सरकार के इस घटनाक्रम की कड़ी आलोचना करते हुए आंतरिक सुरक्षा के निरंतर गिरावट के मद्देनजर धारा ३५५ के तहत कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के नेतृत्ववाली केंद्र की यूपीए सरकार, जिसे सीपीएम का समर्थन प्राप्त है, ने सीताराम येचुरी के उस बयान को अत्यधिक भय से लिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय शासन लगाया जाएगा तो इसका परिणाम केंद्र की यूपीए सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। इस चेतावनी के बाद केंद्रीय शासन की बात तो दूर, अपने को आम आदमी के साथ कहने वाली कांग्रेस ने नंदीग्राम में पुलिस अत्याचार और गरीब एवं निरीह किसानों की हत्या की भर्त्सना करने से भी साफ इनकार कर दिया। गोल-मोल शब्दों में एक उच्चस्तरीय कांग्रेस दल का गठन कर वहां भेजे जाने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की मांग तक को भी ठुकरा दिया। कांग्रेस नेतृत्व की यह दोहरी नीति उस घटना की याद दिलाती है, जब उड़ीसा के कलिंगनगर में १२ आदिवासियों की पुलिस की गोली से हुई मृत्यु पर कांग्रेस अध्यक्ष चौबीस घंटे के अंदर वहां अपने पहुंच गईं, परंतु १५ निरीह किसानों की नृशंस हत्या और सैकड़ों के घायल होने की खबर की जानकारी होने के बावजूद केंद्र की यूपीए सरकार की अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के प्रधानमंत्री ने वहां जाना तो दूर इस घटना की निंदा करने से भी इनकार कर दिया। जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुप्पी साधे हुए हैं वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रियरंजन दासमुंशी का बयान संसद के गलियारे तक ही सीमित रहा। कांग्रेसी नेता सुब्रत मुखर्जी की गाड़ी नंदीग्राम में प्रवेश के पहले ध्वस्त कर दी गई, परंतु कांग्रेस पार्टी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रश्न इंडोनेशिया के सलीम समूह के लिए १२ हजार हेक्चटेयर जमीन देने या नंदीग्राम में रासायनिक हब की स्थापना का नहीं है, बल्कि उनका यह दृष्टिकोण पश्चिम बंगाल की सरकार और यूपीए गठबंधन के सहयोगियों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस देश के आजाद इतिहास में लोकतंत्र के समक्ष अनेक कठिन परिस्थितियां आई हैं, परंतु इस प्रकार की घटनाओं में राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा टिप्पणी किए जाने की घटना कम ही हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने सरकार से प्रतिवेदन मांगते हुए हत्याओं को 'कोल्ड हॉरर' और दिल दहलाने वाला कहा है। यहां तक की महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल

कलाम ने अपने मेघालय प्रवास के दौरान किसानों की जमीन का सरकार द्वारा कठोरतापूर्वक अधिग्रहण किए जाने एवं किसानों को उचित मुआवजा न दिए जाने पर अपनी चिंता जताते हुए नंदीग्राम की घटना को अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया।

पिछले साठ वर्षों से औद्योगिक विकास के लिए जमीनों का अधिग्रहण तो होता ही आ रहा है, परंतु ऐसा क्या कि पश्चिम बंगाल में दो स्थानों सिंगुर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण करने पर किसानों और मजदूरों ने सरकार का जमकर प्रतिरोध किया और फलस्वरूप किसान संगठित और आंदोलित हुए? नंदीग्राम की घटना पूरे तौर से जोसेफ स्टालिन द्वारा रूस में किए गए अत्याचारों का दूसरा रूप पश्चिम बंगाल में प्रतिबिंबित करती है। हम सन १९८९ में चीन में थ्येन आन मन चौक पर प्रदर्शनकारियों को टैंकों से रात के अंधेरे में रौंदे जाने की घटना दुनिया की वामपंथी सरकारों की निर्दयता को पूरी तरह से दर्शाती है। रात तो दूर नंदीग्राम में यह अत्याचार दिन के उजाले में किया गया। गरीब किसानों एवं सिद्धांत की बात करने वाली पार्टी अब तो संसद के भीतर भी ऐसे ही तेवर दिखा रही है। पिछले दिनों सीपीएम ने अपनी सरकार के सहयोगी डीएमके के मंत्री टीआर बालू के सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक पेश करने के दौरान लोकसभा में हाथापाई की नौबत उत्पन्न कर दी थी। यह बात जगजाहिर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य ने गरीब किसानों को सबक सिखाने का बीड़ा स्वयं उठाया है। यह सिलसिला सिंगुर से ही चला आ रहा था और नंदीग्राम में सरकार की पूरी जानकारी में सीपीएम कैडर ने पूरा तांडव किया। असल में पहली बार किसानों ने वहां के नेतृत्व को चुनौती दी थी और यह दमन मात्र उनके विरोध को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए किया गया। लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। नंदीग्राम में पत्रकारों को मारा-पीटा गया। सिंगुर में भी प्रवेश से उन्हें रोका गया था। अब तो चर्चा इस बात की भी है कि कॉमरेडों ने पुलिस की आड़ में हत्या के अतिरिक्त महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया। वामपंथियों के सैद्धांतिक ढकोसले का पिटारा अब खुल गया है। आजाद भारत में इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है कि एक प्रांत में तालिबानी हुकूमत कायम हो गई है और केंद्र की यूपीए सरकार मूकदर्शक बनकर यह सब देख रही है। क्या सरकार गंवाने से अच्छा आंख में पट्टी लगा लेना है?

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं।)

■

उदारीकरण को लाल सलाम की हकीकत

& i"i:'k iir

पश्चिम बंगाल में एक युग से साम्यवादियों की सरकार राज कर रही है। वामपंथी गठबंधन के मुखिया की हैसियत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार रहा है। लगता है कि वर्षों से किसी भी चुनौती के अभाव में इस दल के नेताओं ने यह बात मान ली थी कि उनकी हस्ती तब तक रहेगी जब तक सूरज-चांद रहेगा और उनके तेवर पुराने इंकलाबी नारे को एक करामाती जादुई मंत्र मानने वाले रहे हैं- जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। उनके समर्थकों को यह लगता रहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल में लाल परचम लहरा रहा है तब तक पार्टी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालांकि बाकी देश में (बीच-बीच में केरल के अपवाद को छोड़कर) मार्क्सवादी साम्यवादियों को कोई नामलेवा तक बाकी नहीं है। एक जमाना था, जब औद्योगिक शहर कानपुर से मार्क्सवादी सांसद चुनकर लोकसभा तक पहुंचते थे और अन्यत्र भी पार्टी का संगठन जनाधार के साथ सक्रिय दिखाई देता था। इस बात का नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि संगठित श्रमिकों की पक्षधरता में यह पार्टी कभी पीछे नहीं रही और सीटू जैसे श्रमिक संगठनों ने चुनावी राजनीति से इतर समता की लड़ाई को धारदार बनाया है। मार्क्सवादी पार्टी ने देश में फैलते सांप्रदायिकता के जहर पर काबू पाने में तमाम दूसरी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को वास्तव में जरूरत के वक्त मदद दी है। कुल मिलाकर इस दल की भूमिका आधुनिक-वैज्ञानिक सोच को फैलाने वाली रही है, पर जाहिर है कि आज पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को नेतृत्व इस बात के प्रति बिल्कुल लापरवाह है कि यह साख पलक झपकते नादानी से गवांई जा रही है। वैसे नादानी शब्द का प्रयोग बिल्कुल अटपटा लगता है, क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटा है, उसे देखकर ही लगता है कि तमाम फैसले लाल सलाम का काम तमाम करने वाले अनजाने में या अज्ञानवश नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि सोची-समझी रणनीति का नतीजा है।

जो कुछ सिंगुर और नंदीग्राम में घटा उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। भारत के आजादी के साठ साल बाद और अहिंसक सत्याग्रह

की शताब्दी वाले वर्ष में निहत्थे किसानों पर गोलीबारी और निरंकुश ही कहा जा सकता है। कुछ बातें तत्काल साफ करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार और मार्क्सवादी पार्टी के मुखर नेताओं का कहना है कि पुलिस को आत्मरक्षा में हिंसक भीड़ पर गोली चलानी पड़ी। पुलिस तो उकसाने-भड़काने वाली हरकतों के लिए उन गैर सरकारी संगठनों के जुझारू जुलूसों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने नंदीग्राम में सेज की स्थापना का विरोध करने का बीड़ा उठाया है। टेलीविजन के पर्दे पर जो चित्र देखने को मिले हैं, उनमें निहत्थी औरतों पर लाठी भांजते पश्चिम बंगाल के बहादुर पुलिस-सिपाही ही नजर आते रहे हैं, लामबंद बागी भीड़ नहीं। पथराव करने वालों में भी वर्दीधारी सिपाहियों की संख्या गुस्साए किसानों से कहीं ज्यादा दिखाई दी। इससे भी पहले यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या नंदीग्राम की नाजुक और विस्फोटक स्थिति को देखते हुए भी किसानों को सबक सिखाने पर आमादी पुलिस बल वहां पठाने की क्या जरूरत थी? मार्क्सवादी पार्टी के बचाव में इस घड़ी यह दलीलें सुनने को मिल रही है कि उस इलाके में घोर अराजकता का माहौल बन चुका है और इसके चलते सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं बच रहा था। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी राज्य की सरकार शांति और सुव्यवस्था बनाने में अक्षम प्रमाणित हो, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मगर इस बिल्ले के गले में घंटी लटकाने का जोखिम उठा सकने का जिगरा किस माई के लाल में है? निश्चय ही विद्वान और सौम्य नेकनीयत अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती केन्द्र में उनकी यूपीए सरकार मार्क्सवादियों के समर्थन पर ही टिकी है और इस पार्टी के नेतओं की भौंहे ऊपर चढ़ते ही उनके कश्ती भंवर में डोलती नजर आ जाएगी। कड़वा सच यह है कि मार्क्सवादियों की कृपा से ही उत्तर प्रदेश की कांग्रेसियों के लाख हाथ-पैर मारने के बाद भी मुलायम सिंह की सरकार बची रह सकी थी। ऐसा जान पड़ता है कि जब तक केन्द्र की यह साझा सरकार, जिसमें कांग्रेसियों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है और भाजपाई भगवे ब्रह्मास्त्र से बचाने वाला कवच मार्क्सवादी प्रदान कर रहे हैं, तब तक पश्चिम बंगाल की सरकार को मनमानी करने की खुली छूट मिलती रहेगी।

इस बहस में फंसने से कुछ हासिल होने वाला नहीं कि सारा बवाल बुद्धदेव बाबू की उतावली और जिद्द से पैदा हुआ है, यदि गरीबों के मसीहा नब्बे की दहलीज पार कर चुके ज्योति बाबू आज भी इस कुर्सी पर बिराज रहे होते तो यह दर्दभरी दास्तान देखते को न मिलती। हकीकत यह है कि उदारीकरण, पूंजी निवेश और श्रमिक संगठनों को अनुशासित करने के मामले में पश्चिम बंगाल की साम्यवादी सरकार हमेशा ही दोहरे मानदंडों

वाला पाखंडी आचरण करती रही है। हरियाणा में होंडा फैक्ट्री में मजदूरों पर मालिकों-प्रबंधकों और सरकार के गठबंधन द्वारा ढहाए जाने वाले जुल्मों के खिलाफ जो नेता बढ़-चढ़ कर बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में किसानों मजदूरों पर होने वाले अनाचार-अत्याचार का जिक्र करते ही उन्हें साप सूंघ जाता है। यह मानना कठिन है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ असंतोष या आक्रोश देखने-सुनने को मिलता रहा है, वह सिर्फ एक कर्कश फितरती ममता बनर्जी की शरारत का नतीजा है। आज सिंगुर और नंदीग्राम के बाद मार्क्सवादियों के अन्य सहयोगी दलों की हालत सांप-छूछुंदर वाली हो चुकी है- मार्क्सवादियों के फैसले न निगलते बन पड़ते हैं न उगलते। देश की राजधानी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तथाकथित आलाकमान भी सदमें-सकते में है। यह मामला निठारी से कहीं ज्यादा संगीन है और देर-सवेर सोनियाजी के सलाहकारों की यह तय करना ही होगा कि उनसे क्या बयान दिलवाएं या पश्चिम बंगाल के दौरे मे दूसरे दलों के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शिरकत करें या नहीं। चलते-चलते यह बात उजागर करना भी बेहद जरूरी है कि यह सवाल भारतीय मार्क्सवादी-साम्यवादी पार्टी में पीढ़ियों के संघर्ष का या व्यक्तित्व के टकराव का या चोटी के नेतृत्व के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा का नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वहारा के प्रति संवेदना सहानुभूति रखने वाले सिर्फ ज्योति बाबू कॉमरेड सुरजी या अच्युतानंदन की ही पीढ़ी के सभी कॉमरेड आंख मूंद कर औद्योगिकीकरण और पूंजी निवेश के समर्थक हैं। यदि सीताराम येचुरी अपेक्षाकृत अधिक उदार लचीले नजर आते हैं तो प्रकाश कारत उतने ही कट्टर और विचारधारा की पवित्रता को अक्षत रखने के हिमायती दिखलाई देते हैं। ■

खेती और उद्योग में टकराव ठीक नहीं

& vkykd ijkf.kd

एक साथ बहुत कुछ हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। नंदीग्राम में पिटते किसान और लाशों को देखकर तो यही लगता है कि भारत, अफ्रीका का कोई देश है, जहां कोई तानाशाह अपनी जिद में कितनों को भी मार सकता है। उधर, गुजरात से खबरें आ रही हैं कि आईआईएम अहमदाबाद के कई ग्रेजुएटों को लाखों नहीं, करोड़ों रुपये सालाना की नौकरियां ऑफर की जा रही हैं। तय करना मुश्किल है कहां जाएं। इतने ऑफर, इतने रुपये। सिंगापुर से लेकर न्यूयॉर्क तक सब जगह से आमंत्रण हैं। अहमदाबाद से न्यूयॉर्क तक का यह सफर निश्चय ही सुखद है। पर इस रास्ते में कहीं नंदीग्राम भी आ जाता है। बुद्धदेब भट्टाचार्य कई किसानों की मौत के बाद कह रहे हैं कि अब वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनेगा। आम जनता को समझने वाले कैसे वामपंथी मुख्यमंत्री हैं कि जनता क्या चाहती है, यह भी नहीं समझ सकते। ममता बनर्जी पर पूरा इलजाम थोपना बेवकूफी है। ममता पब्लिक को तभी भड़का सकती हैं, जब वह भड़कने को तैयार हो। नेता पब्लिक की भावनाओं से खेल तो सकते हैं, पर उन्हें बनाने का बूता आज के नेताओं में नहीं है। अब डिबेट चल पड़ी है कि कृषि बनाम उद्योग में क्या होना चाहिए। खेती या उद्योग, दोनों में से क्या होना चाहिए।

यह डिबेट भी मुख्यमंत्री के रुख की तरह ही बेतुका है। कृषि बनाम उद्योग की डिबेट अतिवादिताओं को छूती प्रतीत होती है। इसमें संतुलन का अभाव है। एक तरफ वे लोग हैं, जिनके जेहन में रोमांटिक किस्म का एक गांव है, जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। वे चाहते हैं कि यह सीन बदलना नहीं चाहिए। पुराने किस्म के नक्सलवादियों से लेकर नए किस्म के एनजीओ तक सब यही कह रहे हैं। पोस्टर, बुकलेट, गाने, धरना, प्रदर्शन, ये सब इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। विरोध अब खुद में एक बड़ा कारोबार है। इन्हें यह नहीं दिखाई पड़ता कि खेती से आमदनी लगातार कम होती जा रही है। खेती से जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तो दूर, उसे बचाए रखना मुश्किल है। वे यह देखने में असमर्थ हैं कि आज के किसानों की अगली पीढ़ी को जिस दुनिया का सामना करना है, उसमें रोमांटिक किस्म के गांव नहीं हैं, बल्कि

बाजार संचालित कारोबार हैं। वे यह नहीं देख पाते कि किसान जब खुद बाजार जाता है, तो उसे महंगाई का दंश झेलना पड़ता है, पर वह खुद बाजार में अपनी उपज का मूल्य तय करने में समर्थ नहीं है

उसका गेहूं अगर महंगा होता है, तो सरकार आयात कर लेती है। अगर उसका गेहूं बड़ी कंपनियां ऊंचे दाम पर खरीदती है, तो यही विद्वान लोग कहते हैं कि यह सब नहीं चलेगा। खेती में बड़ी कंपनियां आ रही हैं, गलत बात है। दरअसल, खेती बनाम उद्योग की डिबेट निरर्थक ही नहीं, घातक भी है। यहां खेती को दरकिनार करके नहीं, उसे बेहतर बनाकर कुछ हासिल किया जा सकता है। यह रोमांटिक चिंतन से नहीं, खेती को बाजार से जोड़ने से ही हो पाएगा।

अतिवादिता के दूसरे छोर पर वे लोग हैं, जो मानकर चलते हैं कि सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का एजेंट होना चाहिए। टाटा को जमीन चाहिए, तो सरकार को दिलवानी चाहिए। इंडोनेशिया के किसी उद्योगपति को जगह चाहिए, तो सरकार को दिलवानी चाहिए। जमीन दिलवाना भले ही सरकार की जिम्मेदारी हो, पर उचित शर्तें तय करना किसकी जिम्मेदारी है? उद्योग वाले कोई खैरात का काम नहीं कर रहे। वे धंधे के लिए जगह मांग रहे हैं। उद्योगपति जिस जमीन को हासिल करते हैं, उसके भाव कुछ ही वर्षों में आसमान छूने लगते हैं। इसका फायदा किसानों को नहीं होता। किसानों को समझाया जाना जरूरी है कि जमीन देना उनके लिए कैसे फायदे का सौदा है। इसके लिए कुछ रचनात्मक सुझाव सोचे जा सकते हैं। मसलन, जमीन की कीमत के एक हिस्से के तौर पर किसानों को कंपनियों के शेयर मिलने चाहिए। कारोबार बढ़ेगा, तो इन शेयरों के भाव भी बढ़ेंगे। इसका लाभ उन्हें मिलेगा।

यानी सीपीएम को वह लोकतंत्र परेशान कर रहा है, जिसकी अनुपस्थिति चीन में कुछ □ी स□व बना देती है। सीपीएम नेतृत्व वाली सरकार को सारी बातें चीन से ही नहीं, □ारत के दूसरे राज्यों से □ी सीखनी चाहिए।

इस पूरे कारोबार को किसान नहीं समझ पाए, तो कोई बात नहीं। सरकार कोई ट्रस्ट बना सकती है या किसी सक्षम बैंक को यह जिम्मेदारी दे सकती है कि उसे इन किसानों के शेयरों के हितों को देखना है। जमीन की मिल्कियत किसानों के पास ही रह सकती है। जमीन एक ट्रस्ट के पास हो, जो किसानों का हितरक्षक हो। ये ट्रस्ट सौ साल की लीज पर कंपनियों को

यह जमीन दे सकता है। बदले में वह किराया वसूल सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक नियमित अवधि के बाद किराया बढ़ता रहे। कंपनियां मुनाफा कमाएं और उसका एक हिस्सा किसानों में बांटें। इस तरह के और रास्ते सोचे जा सकते हैं। पर ऐसा चिंतन संतुलित रुख की मांग करता है। लेकिन इस पूरे मसले के केंद्र में जो पार्टी है यानी सीपीएम, उसे संतुलित चिंतन और लोकतांत्रिक परंपराओं का अभ्यास नहीं है। माकपा नेतृत्व ने जो फैसला कर दिया, वह लागू किया जाना चाहिए। नेतृत्व तो अपनी स्थिति झटके से बदल सकता है, पर उसके बारे में पब्लिक को समझाने में समय लगता है। कई दशकों से पब्लिक को उद्योग विरोधी राजनीतिक चिंतन की खुराक देने के बाद अगर पार्टी कहती है कि उद्योग के टॉनिक से सेहत सुधर जाएगी, तो इसे हजम करने में लोगों को वक्त तो लगेगा ही। दीगर है कि राज्यों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कॉरपोरेट जमींदारी बताने वाली पार्टी अपने राज्य में इसे जनहितकारी कैसे साबित कर पाएगी, यह लाख टके का सवाल बन चुका है। चीन का उदाहरण सामने रखें, तो साफ है कि वहां भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मामला आसान नहीं रहा है। पर चीन को लोकतंत्रविहीनता के कुछ लाभ उपलब्ध रहे हैं। नंदीग्राम जैसा कोई प्रकरण चीन में आसानी से संभव नहीं था। अगर होता, तो चीन सरकार इसके लिए सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को भी खत्म करने में भी गुरेज नहीं करती। चीन में इसलिए खबरें असंतोष की नहीं, असंतोष को बेरहमी से कुचले जाने की आती है। वहां नंदीग्राम प्रकरण नहीं, थिएनआनमान चौक प्रकरण होते हैं। यानी सीपीएम को वह लोकतंत्र परेशान कर रहा है, जिसकी अनुपस्थिति चीन में कुछ भी संभव बना देती है।

सीपीएम नेतृत्व वाली सरकार को सारी बातें चीन से ही नहीं, भारत के दूसरे राज्यों से भी सीखनी चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र और हाल में तमिलनाडु में कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बड़ी जमीनें ली गई हैं, पर इतनी मार-काट नहीं हुई। नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के नेता सीपीएम की सरकार को बता सकते हैं, पर दिक्कत यह है कि उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, उसे सब कुछ पता है। उसके पास हर सवाल का जवाब है। मुश्किल यह है कि सवाल नए हैं और उनके पुराने जवाब कारगर नहीं हो रहे हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ाते हैं) ■

नंदीग्राम संग्राम से परेशान माकपा सरकार ने घुटने टेके

& euekgu 'kek

नंदीग्राम में किसानों पर पश्चिम बंगाल पुलिस एवं मार्क्सवादी सशस्त्र कैडर द्वारा ढाए गए कहर के खिलाफ देश भर में जो तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई है उससे घबरा कर राज्य में स्थापित किए जाने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता ने राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य के सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर काम रूका रहेगा जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सामाजिक रूप से संतुलित कोई फैसला नहीं लेता। सरकार को इसलिए भी घुटने टेकने पड़े क्योंकि सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के तीन घटकों फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी और सीपीआई ने मोर्चा छोड़ने की धमकी दी है।

इस सरकारी फैसले को खास महत्व इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इसी तरह का ऐलान राज्य सरकार ने सिंगूर में उठे तुफान के दौरान भी किया था मगर जैसे ही वातावरण कुछ शांत हुआ राज्य सरकार ने वहां पर स्थापित किए जाने वाले टाटा कार के प्लांट की स्थापना के लिए भूमि का जबरन अधिग्रहण फिर शुरू कर दिया था।

यह बात दीगर है कि शुक्रवार की सिंगूर में दस हजार किसानों की उग्र भीड़ ने अपनी-अपनी जमीन पर कब्जा फिर कर लिया है। उन्होंने टाटा कंपनी के पहरेदारों और कर्मचारियों को मार-मारकर भगा दिया और पुलिस को भी वहां से दुम दबा कर भागना पड़ा।

जहां तक नंदीग्राम का सवाल है यह क्षेत्र पूर्वी मिदनापुर जिला में स्थित है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में ६० हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके वहां पर रासायनिक उत्पाद बनाने के लिए इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना चाहती है। इस संबंध में उसका मलेशिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सेलम से इकरार भी हो चुका है। यह भूमि बेहद उपजाऊ है और उस पर साल में चार फसलें पैदा होती है। इस भूमि के अधिग्रहण से एक लाख किसान बेदखल होंगे।

इन किसानों में से ७५ हजार मुसलमान और दलित हैं। एक ओर तो

मार्क्सवादी पार्टी ने मुसलमानों के उत्थान के लिए एक खास नीति की घोषणा की है जिनमें उन्हें खास तौर पर ब्याज मुक्त कर्जा देने के साथ-साथ उन्हें शैक्षिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा करार देते हुए उनके लिए आरक्षण की वकालत की है जबकि दूसरी ओर वह गरीब मुसलमानों की रोजी-रोटी छीन रही है। बताया जाता है कि नंदी ग्राम क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का चयन सेलम ग्रुप के विशेषज्ञों ने किया है, क्योंकि यह क्षेत्र कोलकाता और हल्दिया के बीच स्थित है।

इस क्षेत्र के किसानों ने कृषि जमीन रक्षक समिति बनाई है जो कि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण का प्रबल विरोध कर रही है, इसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एवं अन्य गैर वाम दलों का भी समर्थन है। मामला क्योंकि मुसलमानों का है इसलिए मुस्लिम संगठन जमीयत उल-उलमाए भी मैदान में कूद पड़ी है। इसके नेता मौलाना सैफ उल्ला पुराने कांग्रेसी हैं। वह तीन बार विधायक भी रह चुके हैं। इस क्षेत्र के मुस्लिम किसानों में उनकी जबरदस्त पकड़ है।

इस वर्ष के शुरू में भी जब राज्य सरकार ने पुलिस की मदद से जबरन किसानों को जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया था तो पुलिस की गोली से सात किसान मारे गए थे। इनमें से पांच मुस्लिम थे। कुछ दिनों बाद सशस्त्र किसानों ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर चार पुलिस वालों की हत्या कर दी थी।

इस सप्ताह जब सरकार ने किसानों को भूमि से जबरन बेदखल करना चाहा तो किसानों ने सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी। सड़कें खोद डालीं, पुल तोड़ दिए। इन किसानों की मदद के लिए आसपास के क्षेत्रों के किसान भी परंपरागत अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए। किसानों की इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए तीन हजार सशस्त्र मार्क्सवादी कार्यकर्ता दो हजार पुलिस वालों को लेकर दो गांवों में पहुंच गए। कहा जाता है कि पहले सशस्त्र मार्क्सवादियों ने धरना दे रहे किसानों पर लाठियों, भालों, तलवारों और बमों से हमला किया। जब किसानों ने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की और दोनों में खूनी झड़पें शुरू हो गई तो पुलिस भी मार्क्सवादियों की सहायता में मैदान में कूद पड़ी। पहले लाठियां चली फिर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सरकारी तौर पर १५ लोगों की मौत की पुष्टि की गई है जबकि ५० लोग घायल बताए गए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस नरसंहार में कम से कम ५० निर्दोष मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई दर्जन महिलाओं को बलात्कार का शिकार भी बनाया गया। मार्क्सवादियों और पुलिस वालों ने अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए वहां पर मौजूद फोटोग्राफरों और टी.वी. चैनल वालों के

कैमरे छीनकर उनको तोड़ दिया ताकि वह पुलिस और मार्क्सवादी गुंडों की हरकतों का कोई सबूत जनता के सामने पेश न कर सकें। हैरत है कि इस घटना पर प्रगतिशील सैकुलर लोग मौन हैं।

केंद्र की सरकार क्योंकि ६४ वामपंथी सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है इसलिए कांग्रेस ने नंदी ग्राम पर हुई हिंसा पर चुप्पी साध रखी है मगर विपक्षी दलों ने इस नरसंहार के मामले को संसद के दोनों सदनों में उछाला। उनके हंगामा के कारण संसद की कार्यवाही दो दिन तक ठप्प रही। गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने सदन में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पढ़कर ही अपना दामन झाड़ लिया जिसमें यह दावा किया गया था कि उग्रवादी और शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस नंदी ग्राम गई थी। जब सशस्त्र भीड़ ने उस पर हमला किया तो आत्मरक्षा में उसे गोली चलानी पड़ी। यह दलील आज तक प्रशासन अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने और पुलिस जुल्म पर लीपापोती करने के लिए देता आ रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम में हुए नरसंहार की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने मौका पर जाकर इस नरसंहार में पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।

हालांकि इस सच को हर कोई जानता है कि सीबीआई उसी केंद्रीय सरकार का एक महकमा है जो कि मार्क्सवादियों के इशारे पर नाच रही है इसलिए यह आशा करना गलत होगा कि सीबीआई बंगाल पुलिस और उसके सहयोगी मार्क्सवादी गुंडों के काले कारनामों का पर्दाफाश कर पाएगी।

संसद ने विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवानी के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि नंदी ग्राम के नरसंहार की जांच के लिए एक सर्वदलीय संसदीय टीम मौका पर भेजी जाए।

नंदीग्राम की निरीह जनता पर पुलिसिया जुल्म की पश्चिम बंगाल में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिए तृणमूल कांग्रेस, भाजपा आदि विपक्षी दलों ने राज्यव्यापी बंद का जो आह्वान किया था वह शत-प्रतिशत सफल रहा। सारा जनजीवन पूरी तरह से ठप्प रहा। बंद को राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चक्रवर्ती ने सफलतम करार दिया है। इसका विरोध करने की सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी को भी हिम्मत नहीं हुई जबकि सत्तारूढ़ वाम मोर्चा में शामिल फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका खुलेआम समर्थन किया है इसलिए मार्क्सवादी पार्टी अलग-थलग पड़ गई है। उसे सफाई देना मुश्किल हो रहा है इसलिए पार्टी हाईकमान परेशान है।

राज्य की मार्क्सवादी सरकार राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए औद्योगिकीकरण की गति तेज करना चाहती है इसलिए वह विदेशी

पूंजी निवेश को जरूरी मानती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हर कीमत पर राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं। भले ही इसके लिए उन्हें कितना भी खून बहाना पड़े।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ने के लिए मार्क्सवादी पार्टी ही पूरी तरह से दोषी है। १९६७ में जब अजय बोस की संयुक्त सरकार में पहली बार मार्क्सवादी शामिल हुए थे तो कामरेड जयोति बसु गृह मंत्री बने थे। उन्होंने मजदूरों में मार्क्सवादी पार्टी के कदम जमाने के लिए उग्र मजदूर आंदोलन का समर्थन किया।

मालिकों के घेराव का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह मजदूरों के द्वारा की जाने वाली हिंसा में कोई हस्तक्षेप न करे। श्रमिक अशांति के कारण राज्य के ४७ हजार कारखाने बंद हो गए और ७० लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। मार्क्सवादी पार्टी की सत्ता में पकड़ तो हो गई मगर औद्योगिक दृष्टि से बंगाल तबहा हो गया। उद्योगपति पलायन कर गए और पूंजी निवेश बंद हो गया।

इसी तरह से मार्क्सवादी पार्टी ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ सुदृढ़ करने के लिए भूमिहीन मजदूरों का सहारा लिया। पश्चिम बंगाल में शुरू से ही भूमि बड़े-बड़े जमींदारों के कब्जे में थी। मार्क्सवादी पार्टी ने उनकी भूमि पर खेती करने वाले लाखों बटाईदारों को टेनेंसी राइट दे दिया। इसका असर यह हुआ कि जो लोग बटाईदारों के रूप में रजिस्टर हो गए वही मार्क्सवादी पार्टी का कैडर और शक्ति बने। आक्रामक मजदूर और बटाईदार माक्सर्ववादियों को सत्ता में ले आए और इन्हीं के वोटों के बल पर मासर्क्सवादी गत तीस वर्षों से सत्ता सुख भोग रहे हैं। रजिस्ट बटाईदार भूमि के मालिक नहीं, अगर सरकार सेज के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा इनको नहीं बल्कि असली जमींदारों को मिलेगा जबकि रोजी-रोटी इन बटाईदारों की जाएगी इसलिए वह सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण का उग्र विरोध कर रहे हैं। यही मार्क्सवादी पार्टी का जनाधार है। देश में भूमि अधिग्रहण का कानून तो है मगर पुनर्वास की कोई नीति नहीं। मार्क्सवादी परेशान हैं कि जिस तबके ने उसे सत्ता दी वही अब उसका विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष बिखर चुका है। इससे मार्क्सवादी नेताओं में यह दंभ पैदा हुआ कि राज करने का सदा का उन्होंने ठेका ले रखा है इसलिए वह सिंगूर और नंदी ग्राम से रक्त रंजित होने पर शर्मसार नहीं। ■

वामपंथियों का असली चेहरा बेनकाब

& gjh'k x|rk

दूसरों को गरीबों की भलाई और अच्छी सरकार कैसे चलाएं का उपदेश देने वाले वामपंथियों का चेहरा पहले सिंगूर में और अब नंदीग्राम में सबके सामने आ गया है। पिछले तीस सालों से पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का राज है और पर्दे के पीछे से दिल्ली की सरकार चलाने का उनका काफी तजुर्बा है। १९७७ में उन्होंने समाजवादियों के साथ मिलकर मोरारजी देसाई की सरकार बनवाई थी और फिर गिरवा दी। यही हाल उन्होंने भाजपा के साथ लड़कर वी पी सिंह का किया था। हरकिशन सिंह सुरजीत देवेगौड़ा और आई. के. गुजराल की सरकार चलाते थे और वामपंथी खुलेआम बघारते थे कि किस तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकार गरीबों का ध्यान नहीं रख रही, अमीरों और उद्योपतियों की जेब में है और उन्हीं के हिसाब से नीतियां बना रही है। वामपंथी दिल्ली की सरकार को जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें वैसा उपदेश दे देते थे। वे पाक दामन हैं और बाकी सब गरीबों के दुशमन। जमीन सुधार का जो काम पश्चिमी बंगाल में वामपंथियों ने किया और गरीबों को जमीन बांटी उसका उदाहरण वे पूरे देश के सामने पेश करना चाहते थे। मगर अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। वैसे तो उनका चेहरा पहले ही बेनकाब हो जाता अगर पश्चिमी बंगाल में 'महा-जोत' स्थापित करने की योजना कामयाब हो जाती। कांग्रेस ने 'महा-जोत' में हिस्सा नहीं लिया और पश्चिमी बंगाल में वामपंथियों की दोबारा सरकार बन गई। अगर उस -महा-जोत' में सभी दल मिलकर वामपंथ के खिलाफ मोर्चा खोल देते तो हार निश्चित थी। मगर उनकी किस्मत अच्छी थी के उनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहा। भूमि सुधार उन्होंने किया मगर अब वह एक माफिया का रूप धारण कर चुका है और उसकी परिणति है सिंगूर और नंदीग्राम। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी बंगाल भी बदलाव के लिए बाकी राज्यों की जनता की तरह मचल रहा है। वहां की जनता भी उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में आगे बढ़ना चाहती है। टेलीविजन, रेडियो, अखबारों, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए सूचना जगत में जो क्रांति आई है उसकी वजह से

पश्चिमी बंगाल की जनता भी बदलाव चाहती है। वह भी तरक्की करना चाहती है। मगर तरक्की के लिए पूंजी चाहिए और उद्योगपति, जो तीस साल पहले पश्चिमी बंगाल से भाग गया था वह अभी वापस आने को तौयार नहीं है क्योंकि वामपंथ में ऐसे लोगों की भरमार है, जो न तो बदलाव चाहते हैं और न ही तरक्की करना। मगर वे सरकार से सिर्फ खैरात मांगना चाहते हैं। यानी चिदंबरम कमाएं और पश्चिमी बंगाल को खैरात देते जाएं। ऐसा होता था, ऐसा होता है क्योंकि दिल्ली की केंद्र सरकार को पर्दे के पीछे से वामपंथी चलाते रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों को भी वामपंथियों ने कई बार चलाया है। इंदिरा गांधी को ही अमृतपाद डांगे के समय में वामपंथियों की सुननी पड़ी थी। सिर्फ राजीव गांधी ने इनकी परवाह नहीं की। वरना नरसिम्हा राव भी इन्ही की टोली में शुमार थे और मनमोहन सिंह, चिदंबरम और मोंटेक सिंह आहलूवालिया के होते हुए भी वामपंथी दल पर्दे के पीछे से सरकार को चला रहे हैं मगर सिंगूर और नंदीग्राम ने वामपंथियों का यह चेहरा बेनकाब कर दिया है।

अगर हम इसके आर्थिक पहलुओं को न भी देखें और सिर्फ नंदीग्राम की बुधवार को हुई घटना पर ही टिप्पणी करें तो कुछ तथ्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह घोषणा कर दी थी कि नंदीग्राम में सरकार किसी भी प्रकार की जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी और न ही इस जमीन को किसी भी उद्योगपति को देगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यह भी साफ किया था कि सिंगूर में जो जमीन उद्योगों के लिए मुहैया कराई गई है उसके साथ किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। मगर नंदीग्राम में किसी प्रकार की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसके बावजूद नंदीग्राम में रहने वाले किसानों और वहां की जनता ने पश्चिमी बंगाल सरकार के किसी भी अफसर को वहां पर घुसने नहीं दिया। पिछले दो महीने से उस क्षेत्र में कोई भी सरकारी अफसर नहीं घुस पाया। यही बुद्धदेव भट्टाचार्य की सबसे बड़ी परेशानी थी। अगर उन्होंने घोषणा कर दी कि सरकार किसी प्रकार की जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी तब भी वहां की जनता ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और सरकारी अफसरों को नहीं घुसने दिया तो फिर यह किसका दोष है? नंदीग्राम क्षेत्र से तीन लोकसभा सांसद आते हैं और वे तीनों के तीनों सीपीएम के हैं। गुरुदास गुप्ता उनमें प्रमुख हैं और अगर वे वहां के प्रमुख नेता हैं तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वहां की जनता को न तो सांसद, न ही पार्टी और न ही वहां की सरकार इस बात के लिए राजी कर पाई कि जो वायदे किए गए हैं वे निभाए जाएंगे। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल के पुलिस महाअधीक्षक वही शख्स हैं जिनको बुद्धदेव भट्टाचार्य क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए

खुलेआम लाबिंग कर रहे थे। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट में ही इस समय दो धड़े हो गए है। एक धड़ा दिल्ली में बैठे मार्क्सवादी नेताओं के बिल्कुल खिलाफ है। उनकी यह धारणा बन चुकी है कि दिल्ली के मार्क्सवादी नेता पूरी तरह बिक चुके हैं और इसीलिए उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। नंदीग्राम की जनता आज नेताविहीन है और यही कारण है कि वहां के सांसदों और विधायकों की कोई सुनवाई नहीं है। वहां की जनता ने अपनी एक संघर्ष समिति बना ली है और वह अपना संघर्ष खुद कर रही है। इसलिए बुधवार को जो नंदीग्राम में हुआ वह इस मायने में ऐतिहिासिक है कि सरकार और सीपीए के नेतृत्व में वहां की जनता के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और बुद्धदेव भट्टाचार्य के फरमाबरदार पुलिस महाअधीक्षक ने अपनी योग्यता का सबूत देते हुए लोगों की जान लेने के आदेश जारी कर दिए। यह मिसाल है वामपंथियों के घमंड और सत्ता के नशे की। मेरी जानकारी तो यह भी है कि नंदीग्राम के बारे में बुद्धदेव भट्टाचार्य को कम से कम एक सप्ताह पहले आगाह कर दिया गया था कि वहां ऐसा हो सकता है। नंदीग्राम के संग्राम की पूर्व सूचना आरएसपी नेता अबनि राय ने पहले ही दे दी थी। अबनि राय और बुद्धदेव भट्टाचार्य की आपस में नहीं बनती। मगर फिर भी उन्होंने इसकी पूर्व सूचना सूत्रों के माध्यम से बुद्धदेव भट्टाचार्य को भिजवा दी थी कि वहां गड़बड़ होने की आशंका है।

कुछ लोग वहां पर दंगा कर सकते हैं और सरकार को मुसीबत में डाल सकते हैं। मगर बुद्धदेव हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कुछ नहीं किया। बुधवार की घटना की पूर्व सूचना शनिवार को दे दी गई थी। यह वामपंथियों की गवर्नेंस की जिंदा मिसाल है और सीताराम येचुरी अखबारों में लिखकर मनमोहन सिंह को भाषण दे रहे हैं कि उन्हें कैसे सरकार चलानी चाहिए। समय आ गया है कि वामपंथी भाषण देना बंद करें और सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी एक मिसाल पेश करें। चीन से ही सबक ले लें। उनके टुकड़ों पर पलना बंद कर दें। सीआईए और केजीबी के एजेंटों की बहुत लिस्टें जारी हो चुकी है।

सिर्फ चीन के टुकड़ों पर पलने वालों की जारी होना बाकी है। इसलिए मेरी इन वामपंथियों से गुजारिश है कि वे अब उपदेश न देकर कुछ करके दिखाएं और एक मिसाल पेश करें। पश्चिमी बंगाल बदलाव के लिए मचल रहा है। अगर वामपंथी नहीं बदले तो वहां की जनता उन्हें बदल देगी।

(लेखक जनमत टीवी के डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स हैं।)■

आखिर इस चुप्पी का माजरा क्या है

& vjfon ekgu

नंदीग्राम पर पश्चिम बंगाल की सरकार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण और आश्वासनों का नया दौर शुरू हो चुका है। ऐसा तक भी हुआ था जब सिंगुर के बाद भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वालों की मुहिम नंदीग्राम पहुंची थी और वहां पुलिस तथा माकपा के गुंडों ने उनसे मारपीट की थी। तब भी प्रोफेसर सुमित सरकार और तनिका सरकार जैसे माकपा समर्थक शीर्षस्थ विद्वानों की टिप्पणियों और चौतरफा आलोचना के बुद्धदेव बाबू और माकपा की तरफ से ऐसे ही आश्वासन दिए गए थे। बल्कि एक बार बीच में जब बुद्धदेव भट्टाचार्यने बयान दिया कि अगर नंदीग्राम के लोग नहीं चाहते तो उनके इलाके का विकास करने वाली मौजूदा विकास योजना को छोड़ दिया जाएगा। तब उनके बयान को दो तरह से लिया गया था उल्लेखनीय है कि तब तक वे प्रो. सरकार वगरैह को निजी पत्र लिख चुके थे और यह पत्र अखबारों में आ चुका था। फिर आए उनके बयान को कुछ लोगों में 'हथियार डालना' माना था तो कुछ ने धमकी।

अब हुई घटनाओं के बाद स्पष्ट लगता है कि महीने भर पहले दिया गया उनका बयान विशुद्ध धमकी थी और पर जब सारा मुल्क क्रिकेट वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह देखने की तैयारी में था तो पुलिस और माकपा के गुंडों की फौज ने पूरे इलाके को घेर कर सचमुच का तांडव मचा दिया। हत्या (और अब बलात्कार की बातें भी सामने आई हैं) के साथ-साथ लाशों को ठिकाने लगाने का भी काम हुआ। मीडिया के लोगों की भी पिटाई हुई। हत्याओं में पुलिस की बंदूकों के अलावा दूसरी बंदूकों और हथियारों का इस्तेमाल हुआ। गोलियां लोगों की पीठ पर मारी गई (जाहिर तौर पर वे निहत्थे लोग भाग रहे थे) और कमर के ऊपर लगी है।

और जब राज्यपाल गोपाल गांधी ने इस हत्याकांड पर अपनी राय और 'कोल्ड हॉरर' को सार्वजनिक किया तो माकपा ही नहीं उसके समर्थक माने जाने वाले 'द हिन्दू' अखबार तक ने उनकी आलोचना की। उल्लेखनीय है कि गांधी जी के पौत्र गोपाल गांधी को माकपा अपनी मांग पर पश्चिम बंगाल

ले गई थी। संभवतः गांधी के पौत्र को मार्क्सवादी राज का दरबान या शोभा की चीज बनाने की इच्छा से। पर आखिर गांधी का पौत्र बहुत दिखावटी चीज नहीं रह सकता। गोपाल गांधी ने सरकारी दल, पुलिस और माकपा के गुंडों की इस करतूत पर अपनी राय सार्वजनिक कर अपनी जिम्मेवारियों का बेहतर निर्वाह तो किया ही है, अपना कद भी ऊंचा किया है।

पर मामला माकपा के व्यवहार, 'द हिन्दू' की संपादकीय टिप्पणी, पीयूसीएल, पीयूडीआर जैसे कथित मानवाधिकार संगठनों की डरावनी चुप्पी और वामपंथी राजनीति तथा सोच वाले काफी सोरे लोगों के खुलकर इस घटना के विरोध में आने भर का नहीं है। आज भी माकपा स्टालिनवादी है- सोच और कामकाज की शैली में। ज्योति बसु ने गठबंधन चलाने की जिस अद्भुत पद्धति को विकसित किया आज बुद्धदेव भट्टाचार्य और माकपा ने उसे अपने गुमान में भुला दिया है। सिंगुर और नंदीग्राम जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर गठबंधन के साझीदारों और कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं हुई। अब इसका क्या कारण है या इसका क्या नफा-नुकसान होगा यह हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमारे लिए चिंता की बात है नंदीग्राम और सिंगुर में जारी किसानों, भूमिहीन मजदूरों की दुर्गति। हमारे लिए चिंता की बात है जमीन जैसा साधन किसानों से छीनने से पहले उनसे जरा भी राय न लेने की सोच। हमारे लिए चिंता का विषय है किसानों की तरफ से कंपनियों से मोल-तोल करने का सरकार का फैसला या उलटा करें तो सरकार द्वारा कंपनियों का एजेंट बन जाने का फैसला। जमीन या प्राकृतिक संसाधनों पर किसका हक और कैसा हक या मामला। और इन सबसे बढ़कर चिंता की बात है आर्थिक नीतियों के मामले में सारे राजनैतिक दर्शनों का हथियार डाल देना। अब कम्युनिस्ट शासन किसी निजी कंपनी का 'टेक ओवर' करे या तो स्वाभाविक लगता है पर सरकार और उसका कथित कैडर बड़े व्यावसायिक घरानों के लिए गरीब किसानों का जमीन छीने, इनकार करने पर उन्हें मारे, उनकी औरतों से बलात्कार करें, उनका जीना दूभर कर दें, यह दृश्य अगर बाबा मार्क्स देखते तो जरूर आत्महत्या कर लेते।

सचमुच में कुछ समाजवादी कदम उठाने वाली और संविधान के प्राक्कथन में समाजवाद शब्द जुड़वाने वाली कांग्रेस पार्टी की नरसिंह राव सरकार ने 'चार कदम सूरज की ओर' चलकर जब समाजवाद को दफनाने और नई आर्थिक नीतियों की शुरूआत की तब बहुत ताकतवर ढंग से उभर रही भाजपा और संघ परिवार ने स्वदेशी के नारे पर चुनाव जीता था। अब कांग्रेस सरकार महंगाई, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, शिक्षा जैसे नामों पर नए सिरे से जोर देने और उदारीकरण के बीच संतुलन साधने की बाजीगरी में लगी है तो माकपा और वामपंथी दल आर्थिक नीतियों को जनोन्मुख रखने

का दबाव बनाने का दावा करते रहे हैं।

अब जब माकपा की आर्थिक सोच का यह नमूना सामने आ रहा है तो टाटा और सलेम समूह के लोगों को सुखद हैरानी भले हो सकती है, काफी सारे लोगों को सदमा लगा है। दिलचस्प बात यह है कि अपने लगभग ४५ साल के वजूद में माकपा ने अपनी किसी नीति या फैसले को लेकर माफी मांगने या बदलाव करने की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। माकपा ने १९४२ की अपनी भूमिका से लेकर आपतकाल की भूमिका के लिए भूल स्वीकार की है। माकपा चीनी हमले से लेकर स्टालिन समर्थन तक पर अपनी लाइन बदलने को तैयार नहीं है। और जहां बदलावा किया भी है वहां 'नए मुल्ला के ज्यादा प्याज खाने' की तरह हत्या, बलात्कार, जोर-जबरदस्ती, सबका सहारा लिया जा रहा है पर अपनी नीतियों में 'बदलाव' की बात स्वीकार करने में भी शर्म आ रही है।

माकपा को शर्म आए, उनके वामपंथियों साथियों को उन्हें दबाने का अवसर मिले, पीयूसीएल-पीयूडीआर को नंदीग्राम में ग्रामीण अधिकारों का हनन न लगे, 'द हिन्दू' को इस मामले में सबसे अखरने वाली चीज राज्यपाल का व्यवहार लगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। असली चीज है शासन दलों या मुख्यधारा की राजनीति और पूरे शासन तंत्र का आम लोगों से बेपरवाह हो जाना। लोग बार-बार चुनाव के जरिए, जो उनके लिए संदेश देने का एकमात्र उपलब्ध ताकतवर तरीका है, अपना संदेश दे रहे हैं पर ऊपर बैठे लोग इसकी परवाह नहीं करते। भूमंडलीकरण की ताकतों को प्रबल राष्ट्रवाद और हिन्दुवाद से ही नहीं मार्क्सवाद से तालमेल बैठाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मंडल से निकली पूरी सामाजिक ऊर्जा ध्वस्त या बिखर गई है और मंडलवादियों को इस व्यवस्था की खुरचन के लिए होड़ लगाने में कोई शर्म नहीं आ रही है। नंदीग्राम पर लालू यादव या मुलायम सिंह यादव को माकपा का समर्थन करने से क्या मिलने वाला है (या शिक्षा में आरक्षण पर मोइली कमेटी कर रिपोर्ट का समर्थन करने से) यह समझना मुश्किल है। इसलिए एक नंदीग्राम या सिंगुर का मामला नहीं है। असल में ये बड़ी बीमारियों के संकेत भर हैं।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)■

नंदीग्राम में यह क्या हो रहा है कॉमरेड?

& fu'khFk tk'kh

बंगाल से गुलामी के दौर में एक नारा उभरा था, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' आजाद हिंद फौज के नेता जी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी हर भारतीय की शिराओं में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है। नेता जी का नाम आते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आज पश्चिम बंगाल में एक नया दौर उभरा है, जिसमें एक तरह से कहा यह जा रहा है कि किसानो, हमें जमीन दो और विरोध किया, तो गोलियों से भून देंगे। नंदीग्राम में१४ तरीख को किसानों के साथ जो हुआ, वह अंगरेजी शासनकाल की याद दिलाता है, जब नील की खेती करने वाले किसानों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था।

नंदीग्राम में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की, यह तर्क अगर सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की दृष्टि से सही मान भी लिया जाए, तो लाश उठाकर ले जाने का प्रयास कर रही महिलाओं, बच्चों को बुरी तरह पीटने को मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनके वामपंथी साथी कैसे सही ठहराएंगे? यह वही सरकार है, जो किसानों और मजदूरों के नाम पर चुनकर सत्ता में आती रही है। जिस पश्चिम बंगाल में २२ वर्षों से किसानों की बदौलत लाल परचम फहरा रहा है, वहां की धरती किसानों के खून से लाल करने के कलंक को माकपा अपने माथे से कभी नहीं धो पाएगी। पुलिस ने यह गोलीबारी एक विदेशी कंपनी के लिए उपजाऊ जमीन अधिगृहीत करने का विरोध कर रहे किसानों पर की, वह भी विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) का विरोध कर रहे निहत्थे किसानों पर। माकपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ मिलकर किसानों पर जिस तरह से फायरिंग करते हुए कई टीवी चैनलों पर दिखाया गया है, उसने किसानों और मजदूरों के प्रति पार्टी की विचारधारा और हकीकत की पोल खोलकर रख दी है

यह अजीब है कि किसानों के बल पर सत्ता पर काबिज माकपा किसानों को बेदखल करने का काम कर रही है। सेज के लिए वह राज्य की हजारों एकड़ बंजर जमीन भी दे सकती थी। लेकिन वह तो विश्व बैंक और केंद्र

सरकार के एजेंडे पर चल रही है

और तो और, सिंगूर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल से लेकर संसद तक हुए हंगामे और बवाल के बावजूद यह सब हुआ। आखिर सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? कॉमरेडों को सोचना पड़ेगा कि नंदीग्राम जैसी घटना पश्चिम बंगाल में आखिर हो ही क्यों रही है? राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बड़े उद्योगों को वापस लाना सरकार की नीति और समय की मांग हो सकती है, पर क्या इसके लिए उन्हें छोटी जोत वाले किसानों की उपजाऊ जमीन ही मिली? क्या माकपा सरकार और उसके नीति निर्धारकों ने केंद्र सरकार के पिछलग्गू बनने के अलावा पश्चिम बंगाल की समस्या के बारे में ईमानदारी से सोचा? अगर सोचा होता, तो निश्चित तौर पर बंगाल में हजारों एकड़ पड़ी उस बंजर जमीन पर उसकी नजर जाती, जो किसी काम की नहीं है। इसका अधिग्रहण कर एक तरफ सरकार किसानों को मुआवजा देकर दूसरी जगह जमीन खरीदने और उन्हें स्थापित होने का मौका दे सकती थी और दूसरी तरफ, किसानों की उपजाऊ जमीन भी बच जाती। लेकिन सत्ता में बैठे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट संभवतः सरकार पर भारी पड़े। पिछले बाईस साल के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में कितने वामपंथी नेता अमीर बन गए, क्या कभी इस पर माकपा ने विचार किया है? निश्चित तौर पर हालात वैसे ही हैं, जैसे कभी रूस में जारशाही के दौरान हुआ करते थे। जारों के खिलाफ क्रांति ने वामपंथी विचारधारा को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया था। महान चिंतक कार्ल मार्क्स के जिस दर्शन को लेनिन ने व्यावहारिकता में उतारा था, माकपा ठीक उसके उलटा कर रही है। वैसे तो यह लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि राज्य के किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है। जारशाही के दौरान भी सबसे ज्यादा शिकार किसान ही बनते थे। गुलामी के दौर में अंगरेजों ने भी किसानों को ही निशाना बनाया था। आज माकपा भी यही कर रही है, तो फिर वह अपने और उन लोगों में अंतर को कैसे प्रमाणित करेगी? माकपा सरकार उसी खुली आर्थिक नीति के नाम पर यह सब कुछ कर रही है, जो विश्व बैंक और अमेरिका से आयातित है। सरकार को पहले यह देखना चाहिए कि जो देश इन नीतियों को हम पर लाद रहे हैं, वे अपने किसानों का कितना ख्याल रखते हैं। वे ऐसे देश हैं, जो किसानों को हर तरह की सहूलियत देते हैं। उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण उनके लिए पाप है। हर तरह की सबसिडी किसानों को देकर उनके उत्पाद विकासशील देशों में बेचने के लिए उन देशों में तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। हमारे यहां ठीक इसके विपरीत हो रहा है। केंद्र में सत्ता को समर्थन दे रही माकपा विभिन्न मुद्दों पर अपने सुर तो विरोधी करती है, लेकिन चाटुकारिता उसी सरकार की करती है। एक किस्सा

याद आ रहा है। एक ट्रेन में एक परिवार सफर कर रहा था। सीट रिजर्व थी। एक पहलवान आकर सीट पर बैठ गया। परिवार के मुखिया से नहीं रहा गया। उसने पहलवान से लड़ाई कर ली। पहलवान ने उसे एक झापड़ रसीद कर दिया। फिर मुखिया ने चैलेंज किया कि मुझे पीटा, लेकिन मेरी पत्नी को पीटकर दिखाओ, तो जानें। पहलवान ने उसे भी पीट दिया। परिवार के मुखिया ने एक-एक करके अपने बच्चों और सभी परिजनों को पिटवा दिया। फिर वह शांत होकर बैठ गया। जब दूसरे मुसाफिरों ने पूछा कि तुमने सबको क्यों पिटवाया, तो वह बोला, अब घर जाकर ये मुझे कैसे चिढ़ाएंगे? यही हाल माकपा के नेताओं का है। तमाम मुद्दो पर कांग्रेस माकपा नेताओं की मांगों को दरकिनार कर उनकी पिटाई कर चुकी है। गुड़गांव के जिस मामले को लेकर माकपा ने हाय-तौबा मचाई थी, उसका क्या हुआ? क्या दोषियों को सजा मिली? कथनी और करनी में इस अंतर के चलते आने वाले दिनों में अगर पश्चिम बंगाल से लाल झंडे को वही किसान और मजदूर उखाड़ फेंकें, जिन्होंने अपने खून से सींचकर इसे गांव-देहातों तक फैलाया है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

माकपा सरकार का तर्क है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। प्रकाश करात भी सारा आरोप तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पर मढ़ रहे हैं। इससे यह तो जरूर तय हो गया कि ममता का कद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा हो गया है कि पूरी वाम सरकार के हौसले पस्त हैं। सरकार में शामिल वामपंथी दलों में भी इस कांड को लेकर नाराजगी है। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि ५,००० पुलिस कर्मियों की फौज नंदीग्राम में आखिर भेजी क्यों गई? क्या सरकार ममता बनर्जी पर किए गए माकपा कार्यकर्ताओं के हमले और पत्रकारों की पिटाई को उचित ठहराएगी? साथ ही, क्या माकपा अपने उस आचरण की समीक्षा करने की हिम्मत जुटाएगी, जिसके चलते वह मार्क्सवादी लबादा ओढ़े स्टालिन, ट्रॉस्टस्की और माओ की विचारधारा पर चलने वाली नजर आने की कोशिश करती है?

(लेखक अमर उजाला से जुड़े हैं)■

जमीन का झगड़ा कहां आ पहुंचा

& fnyhi eMy

अगर सलीम ग्रुप लोगों से बाजार भाव पर जमीन खरीद कर नंदीग्राम में अपना केमिकल प्रोजेक्ट लगाता, तो लोगों का गुस्सा शायद इस तरह नहीं फूटता। नंदीग्राम उन तमाम गड़बड़ियों का प्रतीक है, जिनकी वजह से देश में सेज (स्पेशल इकनॉमिक जोन) नीति और जमीन अधिग्रहण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नंदीग्राम उस गड़बड़ी का भी प्रतीक है, जिसने पश्चिम बंगाल की लेफ्ट फ्रंट सरकार को अपनी चपेट में ले लिया है। और फिर दोष लेफ्ट सरकार ाके ही क्यों दें? गाजियाबाद में यूपी सरकार हाई टेक सिटी बनाने के लिए किसानों से सरकारी रेट पर जमीन ले रही हैख लेकिन यमुना किनारे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बनाने के लिए अपनी जमीन बाजार भाव से कम पर देने के लिए तैयार नहीं है। सरकारा लोकहित के लिए जमीन ले सकती है और इसके लिए देश में एक कानून है। लेकिन अगर सरकार जमीन को लेने और देने में अलग-अलग पैमाने अपनाए, तो इसमें लोकहित कहां है?

नंदीग्राम में बंगाल सरकार की नीयत अगर शक के दायरे में है, तो इसकी ठोस वजहें हैं। केमिकल हब बनाने के लिए इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को जमीन चाहिए। इसके लिए उसने ऐसा इलाका चुना जो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह के बीच में है। यह जमीन उपजाऊ है और खेती यहां के लोगों का मुख्य रोजगार है। उजड़ने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सलीम ग्रुप या सरकार क्या करेंगे, इसका आश्वासन देने के लिए कोई तैयार नहीं। वैसे भी इस देश में जमीन अधिग्रहण का तो कानून है, लेकिन पुनर्वास का नहीं। पुनर्वास की नीतियां होती हैं, लेकिन नीतियों को लागू करने की मजबूरी नहीं होती। ये सरकार की सदिच्छा पर निर्भर करती है। नंदीग्राम में इसी सदिच्छा का अभाव नजर आता है।

यहां यह सवाल भी उठता है कि जमीन अधिग्रहण तो देशभर में हो रहा है, लेकिन इतनी तीखी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में ही क्यों नजर आ रही है? दरअसल इसकी वजह बंगाल के भूमि संबंधों में है। लेफ्ट के लंबे शासन में जमीन के मालिकों के अलावा बटाई पर खेती करने वालों का एक ताकतवर तबका उभरा है। ऑपरेशन बरगा के तहत बटाई पर खेती करने वालों को टनेंसी राइट दिए गए। इसका असर यह हुआ कि जो लोग बटाईदार के तौर पर रजिस्टर किए गए, उन्हें इस हक से बेदखल करना मुश्किल हो गया। दरअसल बटाईदार ही खेतों के मालिक बन गए हैं, लेकिन कागजों में मालिकाना हक उनके पास नहीं है। ये बटाईदार ही बंगाल में सीपीएम की राजनीतिक ताकत हैं।

अब जब सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है या करेगी, तो मुआवजा पुराने मालिक को मिलेगा, जो दरअसल खेती कर नहीं रहा है। उनके हिसाब से

तो जमीन उनके नहीं बरगादार के काम आ रही है, इसलिए जब सरकार मुआवजा देती है, तो वह राजी-खुशी इसे लेने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि सिंगुर में सरकार ने आसानी से ६० फीसदी जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन चूंकि बरगादार और खेत मजदूरों को बहुत कम मुआवजा मिल पाता है, इसलिए वे जमीन पर कब्जे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सिंगुर में यही हुआ और नंदीग्राम में यही होने का डर है। सीपीएम के लिए यह एक अजब हालत है। जिस तबके को उसने ताकत दी और जिससे ताकत ली, उसी के हितों पर अब टकराव हो रहा है। वह ऐसी नीति पर चल रही है, जिसका विरोध उसके पक्के वोट बैंक की तरफ से ही आ रहा है। इनमें ज्यादातर लोग दलित या मुसलमान हैं। यह बात सिंगुर से लेकर नंदीग्राम तक मरने वालों की लिस्ट देखकर समझ में आ जाती है। दरअसल सिंगुर और नंदीग्राम में सीपीएम के जनाधार का खून बह रहा है। यही बात सीपीएम के लिए परेशानी की वजह बन सकती है।

पश्चिम बंगाल सरकार दरअसल एक दुविधा में फंस गई है। यह राज्य एक समय औद्योगिक तौर पर सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता था। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के तीस साल के शासन में यह खासा पीछे चला गया। सन १९९१ के बाद देश में विदेशी पूंजी आने का जो सिलसिला चला, उसमें भी बंगाल की हिस्सेदारी नहीं हो सकी। प्राइवेट कंपनियां बंगाल से कतराने लगीं। इसकी एक वजह बंगाल का आक्रामक मजदूर आंदोलन था, जिसकी कमान वामपंथी ट्रेड यूनियनों के हाथ में थी। नए उद्योगों के न आने और पुरान उद्योगों के बीमार पड़ने या राज्य से बाहार चले जाने की वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब लेफ्ट सरकार इस हालत को बदलना चाहती है। उसने जता दिया है कि मजदूरों का हड़ताल पर चले जाना उसे पसंद नहीं। इसका असर दिखा है और बंगाल में औद्योगिक पुनर्जागरण हो रहा है। अब सेज की होड़ मची है और बंगाल सरकार इसमें पीछे रहना नहीं चाहती। उसे इसमें खतरा नजर आता है। इसलिए किसानों में जमीन लेकर उद्योगों को देने के मामले में वह कांग्रेसी सरकारों से भी ज्यादा तेजी दिखा रही है।

इससे अब तक स्थापित राजनीतिक संतुलन और शासन के कायदों में उथल-पुथल मचनी ही है। बुरा यह कि सरकार एक अजीब से दंभ के साथ इसे बदलाव को ला रही है। यह दंभ इस बात से पैदा हुआ है कि बंगाल में तो लेफ्ट का ही राज रहेगा। लगातार जीत और विपक्ष में बिखराव के चलते लेफ्ट के कॉमरेडों को ऐसा भ्रम हो जाए, इसमें हैरानी की बात नही। इसीलिए सिंगुर से लेकर नंदीग्राम तक हुए खूनखराबे के लिए सीपीएम माफी मांगती या प्रायश्चित करती हुई नजर नहीं आती। कांग्रेस के लिए यह मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसी स्थिति है। नए आर्थिक सुधारों को लेकर ऊंचे बोल बोलती रही सीपीएम की बोलती आज बंद है। लोकसभा में अपनी मजबूत स्थिति के चलते सीपीएम अब तक कांग्रेस को अपने इशारों पर नचाती रही है। लेकिन अब बाजी पलटती दिख रही है। सीपीएम में इतना दम नहीं बचा कि आर्थिक सुधारों को लेकर कांग्रेस को उपदेश दे सके। इसलिए कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि यूपीए सरकार का बचा वक्त कम से कम इस मोर्चे पर तो शांति से गुजर जाएगा।

लेकिन इस राजनीति से परे जो हो रहा है वह बेहद संगीन है। नंदीग्राम की ट्रैजिडी अगर जमीन के झगड़ों का हल सुझा सके, तो ही देश को चैन आएगा। वरना तो जो होना है, आप देख ही रहे हैं। ■